प्रकाशन का 46 वां वर्ष

शैल समाचार

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई–पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 46 अंक–29 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 26–02 अगस्त 2021 मूल्य पांच रुपए

ममता ने जांच आयोग गठित करके चला मास्टर स्ट्रोक–मोदी के विकल्प हुए सीमित

पैगासस प्रकरण पर

➯ यदि मोदी सरकार की नीयत साफ है तो फिर जांच क्यों नही करवा रही

➯ जब फोन हैक हो जायेगा तो क्या हैकर उसका आपराधिक उपयोग नहीं करेगा

➯ जब आपकी निजता ही नही बचेगी तो आप सुरक्षित कैसे रह पाओगे

➯ क्या ऐसी संभावनाओं से समाज को बचाना सरकार की जिम्मेदारी नही है

➯ यदि किसी आतंकी संगठन के हाथ यह स्वाईवयेर लग जाये तो कौन सुरक्षित बचेगा

➯ क्या ऐसे परमाणु हथियार सुरक्षित रह पायेंगे

शिमला/शैल। जिस पैगासस जासूसी प्रकरण पर विपक्ष की मांग के बावजूद सरकार जांच करवाने को तैयार नहीं हो रही है और हर रोज़ संसद में यह मामला उठ रहा है उसी प्रकरण पर ममता बैनर्जी ने जांच आयोग अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधीश मदन बी लोकूर की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करके मोदी सरकार के हाथ से सारा मामला छीन लिया है। जांच अधिनियम की धारा तीन के तहत गठित इस आयोग को केन्द्र सरकार तभी निष्प्रभावी कर सकती है यदि वह इससे बड़ा आयोग गठित करती है। अधिनियम की धारा चार के इस आयोग को सिविल कोर्ट के अधिकार हालिस रहेंगे। आयोग किसी भी अधिकारी को बुलाने और कोई भी दस्तावेज तलब करने का हक रखता है। इस प्रकरण की जांच की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिकाएं आ चुकी हैं और शीर्ष अदालत ने इन्हे सुनवाई के लिये स्वीकार भी कर लिया है। माना जा रहा है कि जब सरकार संसद में विपक्ष की बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं तब इससे बेहत्तर और कोई उपाय रह नहीं जाता था। सरकार इस मुद्दे को कोई गंभीर मुद्दा ही नहीं मान रही है जबकि इस जासूसी स्पाईवेयर से न केवल आम आदमी की निजता पर डाका डाला गया है बल्कि इससे देश की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा हो जाता है। क्योंकि यह स्पाईवेयर एक विदेशी कंपनी द्वारा बनाया गया है और उसने स्पष्ट कहा है कि स्पाईवयेर वह केवल सरकारों को ही बचेती है। भारत में इसके माध्मय से कई लोगों की जासूसी हुई है। इसका शिकर कई पत्रकार बुद्धिजीवी, उद्योगपति, ज्ज और राजनेता हुए हैं। मोदी सरकार के अपने ही दो मन्त्रीयों की जासूसी हुई है। इस सब पर सरकार केवल इतना कह रही है कि जासूसी में वह शामिल नहीं है। लेकिन जासूसी होने से इन्कार नही कर रही है। विप़क्ष इस परिदृश्य में सरकार से सीधा सवाल पूछ रहा है कि क्या उसने यह स्पाईवेयर खरीदा है या नही। सरकार इसका हां या न में जबाव देने से भाग रही है और इसी से सरकार की नीयत और नीति दोनो ही सन्देह के घेरे मे आ जाते हैं।

क्यों जरूरी है यह जांच

सरकार इसे गंभीर विषय न म ा न क र विपक्ष पर संसद न चलने देने का आरोप लगा रही है। सरकार जनता को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि इस जासूसी प्रकरण से भी ज्यादा गंभीर कई मुद्दे हैं जिन पर संसद में बहस होनी चाहिये। सरकार के कई अन्ध भक्त भी इसे गंभीर विषय नही मान रहे हैं तो आपको ऐसी जासूसी होने से डरने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिये। इसलिये यह समझना आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकरण की जांच होना जरूरी है और आम आदमी इससे कहां प्रभावित होता है। सबसे पहले तो बड़ा खतरा यह है कि इससे व्यक्ति की निजता प्रभावित होती है। यह निजता कितनी महत्वपूर्ण है इसका इसी सूत्र से चल जाता है कि जिसमें कहा गया है कि ‘‘ भोजन, भजन, वस्त्र और नारी यह सब परदे के अधिकारी’’ इस निजता की रक्षा के लिये घरों के दरवाजे खिड़कीयों को बन्द रखने के लिये ‘‘कुण्डी’’ लगाई जाती है परदे लगाये जाते है ताकि दूसरा कोई गैर तांक झांक कर सके। दूसरा खतरा है कि इस जासूसी में आपका फोन हैक कर लिया जाता है और हैकर उसे अपने मकसद के साथ आप्रेट करता है। हर रोज़ फोन हैक होने और आपके परिचितों से आपके नाम पर पैसे मांगने के किससे सामने आ रहे है। हैकर बैंक खातों में सेन्ध लगा रहे हैं इस आशय की साईबर क्राईम में हर रोज़ दर्जनों शिकायतें आ रही हैं। इस हैंकिग से बैंको में हजारों करोड़ के फ्राड हो चुका है।

मोदी सरकार में वैचारिक असहमति हो देशद्रोह करार देने का चलन शुरू हो चुका है। सैंकड़ों मामले देशद्रोह के बनाये जा चुके हैं। सजा केवल छः मामलों में ही हुई है। भाजपा शासित हर राज्य में ऐसे मामले बने हैं। भीमा कोरे गांव प्रकरण में तो यहां तक सामने आ चुका है कि रोमा विलसन आदि के कम्प्यूटरों को हैक करके उनमें आपति जनक सामग्री डाली गयी। इस स्पाईवेयर के माध्यम से किसी के भी फोन में कभी भी कुछ भी आपतिजनक डालकर किसी को भी फेम किया जा सकता है।

शेष पृष्ठ 8 पर.........

यह हैं जांच अधिनियम के प्रावधान

3. Appointment of Commission.—(1) The appropriate Government may, if it is of opinion that it is necessary so to do, and shall, if a resolution in this behalf is passed by 2 [each House of Parliament or, as the case may be, the Legislature of the State], by notification in the Official Gazette, appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into any definite matter of public importance and performing such functions and within such time as may be specified in the notification, and the Commission so appointed shall make the inquiry and perform the functions accordingly. Provided that where any such Commission has been appointed to inquire into any matter—

(a) by the Central Government, no State Government shall, except with the approval of the Central Government, appoint another Commission to inquire into the same matter for so long as the Commission appointed by the Central Government is functioning;

(b) by a State Government, the Central Government shall not appoint another Commission to inquire into the same matter for so long as the Commission appointed by the State Government is functioning, unless the Central Government is of opinion that the scope of the inquiry should be extended to two or more States.

(2) The Commission may consist of one or more members appointed by the appropriate Government, and where the Commission consists of more than one member, one of them may be appointed as the Chairman thereof.

[(3) The appropriate Government may, at any stage of an inquiry by the Commission fill any vacancy which may have arisen in the office of a member of the Commission (whether consisting of one or more than one member).

(4) The appropriate Government shall cause to be laid before 2 [each House of Parliament or, as the case may be, the Legislature of the State], the report, if any, of the Commission on the inquiry made by the Commission under sub-section (1) together with a memorandum of the action taken thereon, within a period of six months of the submission of the report by the Commission to the appropriate Government.]

4. Powers of Commission.—The Commission shall have the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters,\ namely:—

(a)5 [summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India] and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents;

(f) any other matter which may be prescribed.

राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन श्री अरबिंद एण्ड इंडिया रेनिसेंस की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि श्री अरबिंद घोष एक विद्वान, कवि और राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मुक्ति के दर्शन को प्रतिपादित किया। वह न केवल भारतीय क्रांतिकारियों में एक अग्रणी थे, बल्कि दूरदर्शी भी थे, जिन्होंने एक उभरते हुए भारत का पूर्वाभास किया और राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया।

यह बात राज्यपाल ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन श्री अरबिंद एण्ड इंडिया रेनिसेंस विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि श्री श्री अरबिंद का पूरा जीवन बलिदान भरा रहा। उन्होंने कहा कि त्याग अलग-अलग विषयों में अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है लेकिन त्याग की भावना का होना आवश्यक है। मन में त्याग का भाव हो तो सारा संसार तुम्हारा है, क्योंकि जब भी त्याग की भावना होती है, तो उसके दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न विषयों का समाधान किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान की भावना का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब कई आत्माएं त्याग की भावना से आगे बढ़ती हैं, तो समय के साथ राष्ट्र और अधिक सुदृढ़ हो जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का अर्थ है नागरिकों की बलिदान की भावना। राज्यपाल ने कहा कि यदि बलिदान की भावना नहीं होगी तो हमारे जीवन और इसका अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि श्री अरबिंद ने राष्ट्रवाद की विचारधारा और त्याग की भावना का देश में प्रसार किया था। उन्होंने देश की राजनीति में भी बहुमूल्य योगदान दिया। वह आधुनिक भारत के योगी थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज का नारा दिया था। वे कहते थे कि यदि स्वराज पाकर भी आप देश नहीं चला सकते हैं तो फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए श्री अरबिंद ने देश को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कहा कि उनका योगदान अतुलनीय है।

श्री अरबिंद ने कहा था कि देश केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि एक जीवंत राष्ट्र है। राष्ट्र में एक आत्मा होती है, जिसकी चेतना से राष्ट्र विकसित होता है। यदि यह चेतना मर जाती है, तो राष्ट्र टुकड़ों में बिखर जाता है। इसलिए देश को राष्ट्रीय चेतना और नवाचार की आवश्यकता है। उन्होंने यह विचार लगभग सौ वर्ष पूर्व हमारे सामने रखे थे। उन्होंने कहा कि हमें देश से सब कुछ मिला है और जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, तो नागरिकों को देश और समाज में योगदान देने का संकल्प लेना होगा जिससे अन्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

इस अवसर पर उन्होंने महान देशभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

राज्यपाल ने श्री अरबिंद घोष के चित्र और 'हिमांजलि' नामक पुस्तक का अनावरण भी किया।

मुख्य सचिव ने राज्यपाल को बारिश से हुए नुकसान व बचाव कार्यों की जानकारी दी

शिमला/शैल। मुख्य सचिव अनिल खाची ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की।

मुख्य सचिव ने राज्यपाल को प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान तथा प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों के लिए उठाये गए कदमों की जानकारी दी।

राज्यपाल ने मुख्य सचिव को राहत व पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने तथा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

प्रधान सचिव, राजस्व के.के पंत भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

लाहौल घाटी में फंसे लोगों को निकालने के लिए ली जा रही हेलीकॉप्टर की सेवाएं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के नए हेलीकॉप्टर को लाहौल घाटी में फंसे लोगों को राहत प्रदान करने के लिए तैनात किया है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से पांच दिनों तक सड़क मार्ग बंद होने के कारण लाहौल घाटी में फंसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए अधिकारियों को घाटी में हेलीकॉप्टर तैनात करने के निर्देश दिए। इस प्रकार प्रदेश के नए हेलीकॉप्टर की पहली सेवाएं परोपकारी कार्यों के लिए ली जा रही हैं। हेलीकॉप्टर की दिन भर की उड़ानों से तांदी में फंसे सभी लोगों को कुल्लू पहुंचाया जाएगा। कुल्लू से यह लोग सार्वजनिक परिवहन द्वारा अपने-अपने गंतव्य तक पहुंचाए जाएंगे।

स्वास्थ्य संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 24110.40 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित

शिमला/शैल। कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने और स्वास्थ्य संस्थानों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति ने 24110.40 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में कोविड पॉजिटिव मामलों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं की खरीद, बफर स्टॉक के रखरखाव और आवश्यक दवाओं के प्रबंधन के लिए निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और निदेशक, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को 12 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि लाहौल और स्पीति और किन्नौर जिलों के लिए 32 बिस्तरों वाली एक समर्पित बाल चिकित्सा देखभाल इकाई का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, कुल्लू, सोलन, ऊना, जोनल अस्पताल मंडी, धर्मशाला और शिमला, आईजीएमसी शिमला, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मंडी, टांडा, नाहन, चंबा और हमीरपुर के लिए 42 बिस्तरों वाली बाल चिकित्सा देखभाल इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। सिविल अस्पताल काजा, पांगी, उदयपुर, डोडरा, भरमौर, शिलाई, कुपवी, नेरवा और पूह में 20 बिस्तरों वाली इकाइयां प्रस्तावित की गई हैं। यह भी निर्णय लिया गया है कि शिमला, मंडी, टांडा, नाहन, चंबा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों में 20 अतिरिक्त आईसीयू बिस्तर स्थापित किए जाएंगे।

इसके अलावा, नागरिक अस्पताल देहरा, चैपाल, सरकाघाट, करसोग, अर्की, बगश्याड़, घुमारवीं डलहौजी, चुवाड़ी, सराहन और पांवटा साहिब में पांच बिस्तरों वाले आईसीयू भी स्थापित किए जाएंगे। इंदौरा, हमीरपुर और नाहन में 100 बिस्तरों वाले फील्ड अस्पताल प्रस्तावित किए गए हैं। इन गतिविधियों के लिए 11935.39 लाख रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1280 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। नाहन, हमीरपुर, धर्मशाला, ऊना, कुल्लू, बिलासपुर, सोलन, पालमपुर, खनेरी, चंबा, किन्नौर और रिकोंगपियो में 10 किलो लीटर क्षमता के लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है। आईजीएमसी शिमला, नेरचैक और चम्याना में 20 किलोलीटर क्षमता के एलएमओ की यूनिट प्रस्तावित की गई है। सरकाघाट और देहरा के लिए भी एलएमओ प्रस्तावित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य ने पीजी रेजीडेंट, यूजी इंटर्न और एमबीबीएस, जीएनएम और बी.एससी विद्यार्थियों को शामिल करे अतिरिक्त मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है। इसके लिए 2294.10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी 12 जिला अस्पतालों, 36 नागरिक अस्पतालों, आईजीएमसी शिमला की तीन इकाइयों-आईजीएमसी शिमला, केएनएच और चम्याना सहित दो मेडिकल कॉलेजों में ई-अस्पतालों को कार्यान्वित करने के लिए 1428.04 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

राज्य में टेली-मेडिसिन को मजबूत करने की दृष्टि से, मेडिकल कॉलेजों में दो अतिरिक्त हब बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए 43.42 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया है। बाल चिकित्सा कोविड-19 प्रबंधन, आईटी हस्तक्षेप और व्यवसायियों के सीएमई पर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए 96.94 लाख रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा गया है।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on the prescribed form, terms and conditions mentioned in form-6&8 are hereby invited for the following works by the undersigned from the firms/contractors enlisted with PWD(Electrical), so as to reach in the office of the undersigned (1)Tender documents consisting of plans classes of work to be done and set of terms and conditions of contract to be complied with by the contractor/firms whose tender may be accepted and other necessary documents can be seen in the office of the undersigned between hours of **11.00 AM to 4.00 PM** except on Sundays and public holidays. (2) The firm / contractor who are not registered under H.P.General Sale tax Act,1968 and have not cleared all the dues on account of sale tax shall not be issued the tender documents (3) The contractor who has no registration certificate with Excise and taxation department of HP will not be issued the tender documents (4) Tenders placed in sealed envelope with name of work and due date written on the envelope will be received by the undersigned and will be opened by him or his authorized representative in his office in the presence of contractors, present if any. (5)The earnest money in the shape of NSC/Time deposit account / saving account in any of the post offices of HP duly pledged in favour of undersigned must accompany with the tender in the separate envelope. The tenders without earnest money will summarily be rejected. (6)) In case of holiday, the tenders shall be sold/received and opened on the next working day.(7)Tenders of contractors who quote two or more than two rates for any item of work shall be rejected. (8) The competent authority on behalf of Governor of H.P reserves the right to reject any or all the tenders received without assigning any reason. (9) Tender forms shall be sold to only those contractors who deposit earnest money in any of the prescribed modes simultaneously at the time of sale of tender documents.

(i) Last date of receipt of application: 11.08.2021 Up to 1.00 P.M
(ii) Date of sale of tenders 11.08.2021. Up to 2 PM to 5.00 PM
(iii) Last date of receipt of bids: - 13.08.2021 Upto10.30 A.M
(iv) Date of bid opening: - 13.08.2021 AT 11.30 A.M

Work No. (1) Providing A/A in PWD rest house at Sungri Rohru Distt.Shimla (SH:Prov.EI therein)..Estimated cost Rs.2,38,968/-Earnest money Rs.4800/-Time: 3 months. Cost of form Rs.350/NR

Work No. (2) C/O 2Nos.type-III residence Qtrs.of PWD at Rohru Distt.Shimla.Estimated cost Rs.2,95,094/-Earnest money Rs.6000/-Time:6 months. Cost of form Rs.350/NR

Work No. (3) Replacement of wiring and FTL fittings at Harvinton House No.6 residence of Hon"ble justice Satyan Vaidya of HP High Court Shimla..Estimated cost Rs.2,09,500/-Earnest money Rs.4200/-Time: 3 Months. Cost of form Rs.350/NR

Work No.(4) Providing central heating in X/Ray and Lab(old building in civil hospital at Theog(SH:Prov.FCU therein. Estimated cost Rs.4,98,995/-Earnest money Rs.10000/-Time:3 months. Cost of form Rs.350/NR

Work No. (5) Providing electrical connection and earthing for 50KVA DG set at Sarasi Bhawan (dedicated Covid Centre) at R/Peo Distt.Kinnaur..Estimated cost Rs.1,22,558/-Earnest money Rs.2500/-Time:3 month,. Cost of form Rs.350/NR

Work No. (6). Providing street light in campus of boys hostel of Govt.Polytechnic college at Rohru Distt.Shimla (HP) Estimated cost Rs.3,13,274/-Earnest money Rs 6300/-time: 3 months. Cost of form Rs.350/NR.

Work No. (7.) Providing F/S equipment in ITI building at Kumarsain Distt.Shimla.Estimated cost Rs.4,95,588/-Earnest money Rs.10000/-time: 3 month. Cost of form Rs.350/NR

Work No. (8) Providing generator supply and separate light and heating SBD at block-E 3rd floor of IGMC Shimla..Estimated cost Rs.1,28,351/-Earnest money Rs.2600/-Time: 3 months. Cost of form Rs.350/NR

Work No. (9) Providing F/S devices equipment in CHC building at Taklech Distt.Shimla.Estimated cost Rs.4,97,500/-Earnest money Rs.10000/-Time: 3 months. Cost of form Rs.350/NR

Work No. (10) C/O civil hospital building at Theog Distt.Shimla(SH:Prov.hot water, piping and control cable for X/ray and Lab(new building) Estimated cost Rs.4,99,750/-Earnest money Rs.10000/-Time:3 months. Cost of form Rs.350/NR

Work No. (11) C/O Govt.Sr.Secy.School at Dhadi Rawat in Tehsil Jubbal Distt.Shimla.(SH:Prov.balance work therein) Estimated cost Rs.2,48,441/-Earnest money Rs.5000/-Time: 1 year. Cost of form Rs.350/NR

Adv. No. 2809/21-22 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रीना
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer, Palampur Division, HPPWD, Palampur on behalf of Governor of Himachal Pradesh, re-invites the item rate bids, in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table:-

Sr.No.	Name of Work	Estimated cost	Starting Date of downloading Bid	Earnest Money	Deadline for submission of Bid
1.	Annual Surfacing of link road from Arth Jhikli to Ree Gidda road. (SW: Providing and laying 30 mm thick bitumen concrete with paver finisher in Km. 0/00 to 1/500)	Rs 11,08,342/-	12.8.2021	Rs. 22200/-	18.8.2021

The bidders are advised to note other details of tenders from the department website **WWW.hptenders.gov.in**

Adv. No. 2842/21-22 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकासात्मक योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जिला मुख्यालय में लाहौल स्पीति के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, कृषि एवं बागवानी विभाग से बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने वर्ष भर पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित समग्र एवं सतत् योजना तैयार करने के जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के माध्यम से भूमिगत बिजली आपूर्ति केबल बिछाने के संबंध में सीमा सड़क संगठन से लंबित स्वीकृति संबंधी मामले पर चर्चा के लिए जल्द ही बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अति आवश्यक है क्योंकि थिरोट पावर हाउस ही बिजली का एकमात्र स्रोत है।

उन्होंने अधिकारियों को स्पीति उपमंडल में हुई क्षति के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बीआरओ कमांडेंट को उदयपुर क्षेत्र में मुख्य सड़क के जीर्णोद्वार के लिए समय सीमा सुनिश्चित करने को भी कहा।

जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकंडा ने मुख्यमंत्री को सम्पर्क सड़क की समस्या से नकदी फसलों को हुए नुकसान से अवगत कराया।

इस अवसर पर उपायुक्त नीरज कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

इसके उपरान्त मुख्यमंत्री ने थिरोट तक बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लेने के लिए थिरोट तक हवाई सर्वेक्षण किया।

सभी विभाग समयबद्ध निपटाएं मामले, हर 15 दिन में दें प्रगति रिपोर्ट: सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सचिवालय में शिमला स्मार्ट सिटी, वन, लोक निर्माण, केंद्रीय लोक निर्माण और अन्य भागीदार विभागों की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में वन विभाग की स्वीकृति न मिलने से स्मार्ट सिटी के लम्बित कार्यों को लेकर चर्चा हुई। शिमला स्मार्ट सिटी के 6 कार्यों के लिए वन विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता है और 10 प्रकल्पों में पेड़ काटने की अनुमति मांगी गयी है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी का लक्ष्य शिमला शहर को विकसित करना और आधुनिक बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन से सम्बन्धित मामलों को शीघ्र निपटाया जाए और औपचारिकताएं भी समयबद्ध पूरी की जाएं।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि अब वन स्वीकृति के लिए देहरादून कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। शिमला में कार्यालय खुलने से इन मामलों के निदान में तेजी लाई जानी चाहिए।

उन्होंने विभागों से मामलों को सम्बंधित विभाग के साथ समयबद्ध उठाने, कार्य शीघ्र पूरा करने और हर 15 दिन के बाद उन्हें प्रगति रिपोर्ट प्रदान करने के निर्देश दिए।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि रिज की मरम्मत, लक्कड बाजार से रिज के लिए एसकेलेटर, संजौली से आईजीएमसी के लिए स्मार्ट पाथ शहर के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि सभी सम्बंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्य आरम्भ करें।

आठ लाख विद्यार्थियों को हिम तत्पर शिक्षा के साथ योग कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा: गोविन्द सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने समग्र शिक्षा और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में तैयार किए गए हिम तत्पर शिक्षा के साथ योग कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीन परम्परा का अमूल्य उपहार है। योग मनुष्य में शारीरिक और मानसिक

सन्तुलन स्थापित करता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और विद्यार्थियों को भी हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से योग और ध्यान सिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लगभग आठ लाख से अधिक विद्यार्थियों को कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा विभाग के हर घर पाठशाला कार्यक्रम में योग और ध्यान संबंधित वीडियो डाले जाएंगे।

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी में योग आशा की नई किरण बन कर उभरा है। इस महामारी के प्रतिबन्धों और इससे पहुंची क्षति के कारण लोग अवसाद और तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। योग लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है।

इससे पूर्व, शिक्षा मंत्री ने समग्र शिक्षा के डिजिटल साथी अभियान के लिए 50 मोबाइल फोन प्रदान किए। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा इस अभियान के लिए 21 हजार मोबाइल फोन उपलब्ध करवाने की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कारपोरेट घरानों और समृद्ध परिवारों से इस अभियान में बढ़-चढ़ भाग लेने का आहवान किया। इस अभियान के माध्यम से प्राप्त होने वाले मोबाइल फोन अभावग्रस्त बच्चों को वितरित किए जाएंगे ताकि कोरोना के इस संकटकाल में उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने अपने वीडियो संदेश में शिक्षा मंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी योग के प्रति और अधिक जागरूक होंगे। समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक वीरेन्द्र शर्मा, आर्ट ऑफ लिविंग के पदाधिकारी मधुराव, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिया जीएसटी राजस्व की अधिकतम वसूली पर बल

शिमला/शैल। राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग के उत्तरी क्षेत्र की एक समीक्षा बैठक पालमपुर में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जगदीश

चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह बैठक राज्य के कंजंप्शन जिलों से जीएसटी राजस्व की अधिकतम वसूली पर सरकार की अपेक्षाओं की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई।

इस दौरान कांगड़ा, नूरपुर, ऊना और चंबा और उत्तरी प्रवर्तन क्षेत्र के राजस्व जिलों वाले उत्तरी क्षेत्र के जिले के प्रदर्शन की समीक्षा विभिन्न मापदंडों पर की गई। इसमें निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले की गई राजस्व वसूली, रिटर्न दाखिल करने, रिटर्न की जांच और प्रवर्तन कार्रवाई आदि मुद्दे शामिल थे। जगदीश चंद्र शर्मा ने सभी उपलब्ध विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग कर 360 डिग्री विश्लेषण के माध्यम से राजस्व प्राप्ति को अधिकतम करने पर जोर दिया। विभिन्न मानकों पर अगली तिमाही के लिए लक्ष्य उत्तरी क्षेत्र के जिलों को आवंटित किए गए थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिले निर्धारित लक्ष्यों से अधिक प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे और इसे लेकर इसी वर्ष अक्तूबर महीने में समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के राजस्व में विभाग के महत्व को देखते हुए विभाग को हिमाचल प्रदेश राजस्व सेवाओं में संगठित किया है। सरकार विभाग की कार्यप्रणाली में विशेषज्ञता और व्यावसायिकता लाने की दृष्टि से विभाग के पुनर्गठन की प्रक्रिया में है। उन्होंने अधिकारियों को आश्वासन दिया कि उनके विभिन्न मुद्दों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

2023 तक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 22 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत

रोजगार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है ताकि उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें और वे सम्मानपूर्वक आजीविका अर्जित कर सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत www.kaushalpanjee.nic.in में पंजीकरण करवाने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को विभिन्न व्यवसायों जैसे ब्यूटिशन, टेलरिंग, स्टोरेज ऑपरेटर, स्पा इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि योजना के अन्तर्गत अब तक 5320 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिनमें से 3021 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-23 के लिए 22 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना का और अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रचार करने के निर्देश दिए ताकि अधिकतम ग्रामीण युवा इस योजना का लाभ उठा सकें।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की मासिक पत्रिका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का भी विमोचन किया। इस पत्रिका को पंचायत स्तर पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न हितधारकों में वितरित किया जाएगा।

जय राम ठाकुर ने योजना के लाभार्थियों को टी-शर्ट, टोपी और मास्क वितरित कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चिड़ियाघरों में मूलभूत सुविधाएं जोड़ने का आह्वान किया

शिमला/शैल हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर और संरक्षण प्रजनन समिति के गवर्निंग बोर्ड की बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन निशा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

निशा सिंह ने राज्य वन विभाग के वन्य जीव शाखा कार्यालयों और अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य के सभी चिड़ियाघरों में थियेटर, ऑडियो-वीडियो एड्स और बेहतर स्मारिका दुकान जैसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करने का आहवान किया। उन्होंने प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने और चिड़ियाघरों में अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए इन गतिविधियों को पर्यावरण पर्यटन के साथ जोड़ने पर भी बल दिया।

प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल, वन्य जीव अर्चना शर्मा ने बताया कि कुफरी चिड़ियाघर में एक 3-डी थियेटर का कार्य पूरा होने वाला है जिसे बहुत जल्द शुरू किया जाएगा।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल और समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल ठाकुर ने राज्य के विभिन्न चिड़ियाघरों, तीतरों और बंदर नसबंदी केंद्रों में समिति के द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने एचपीजेडसीबीएस की पिछली बैठक पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। गवर्निंग बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एपीओ को मंजूरी दी।

बोर्ड ने चिड़ियाघरों के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराकर चिड़ियाघरों को मजबूत करने का भी निर्णय लिया।

बैठक में प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल डा. सविता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

नीच व्यक्ति के सम्मुख रहस्य और अपने दिल की बात नहीं करनी चाहिए। ......चाणक्य

सम्पादकीय

अवैधताओं और अतिक्रमणों का परिणाम है यह प्रकोप

इस बार भारी वर्षा के कारण जितना नुकसान हुआ है इतना शायद पहले कभी नहीं हुआ है। दो सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। चार सौ से अधिक पशु मर गये हैं। सैंकड़ो कच्चे-पक्के मकानों का नुकसान हुआ है। कई पुल, सड़कें और पेयजल योजनाएं तबाह हो गई हैं। लोक निर्माण और जल शक्ति विभागों का ही अब तक 63289 लाख से अधिक का नुकसान हो चुका है। आम आदमी का कितना नुकसान हुआ है उसका अभी पूरा आकलन नहीं किया जा सका है। जिन परिवारों के लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई शायद कोई भी मुआवज़ा नहीं कर पायेगा। इस नुकसान को देखकर यह सवाल खड़ा होना स्वभाविक है कि क्या इस नुकसान को कम किया जा सकता था। यह सही है कि वर्षा को रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या उसके पानी को चैनेलाईज़ भी नहीं किया जा सकता? इस सवाल पर विचार करते हुए जब यह सच्चाई सामने आती है कि विकास के नाम पर तो हमने स्वयं कई नदियों के प्राकृतिक बहाव के मार्गो को रोक दिया है। धर्मशाला के पास जब अचानक हुई भारी बारिश से पानी का बहाव बदला और उससे भयानक तबाही हुई तब यह सामने आया कि उस पानी के प्राकृतिक मार्ग पर तो कई स्थानों पर अतिक्रमण किया जा चुका था। यदि यह अतिक्रमण न हुआ होता तो शायद इस नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकता था। सिरमौर में राष्ट्रीय राज मार्ग 707 के टूटने का कारण भी भू-गर्भ विशेषज्ञों ने इसके निर्माण में आवश्यकता से अधिक भारी मशीनों के इस्तेमाल को कारण बताया है। जहां-जहां भी नुकसान हुआ है यदि वंहा पर उसके कारणों की समीक्षा की जायेगी तो अधिकांश स्थानों पर प्रकृति से ज्यादा मानव निर्मित कारण सामने आयेंगे।

प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन दिनों भी प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हो रहे अतिक्रमणों का कड़ा संज्ञान लिया है। चम्बा के एक व्यक्ति की याचिका पर उच्च न्यायालय ने प्रदेश भर में हुए अतिक्रमणों का ब्यौरा प्रशासन ने तलब किया है। उच्च न्यायालय इससे पूर्व भी ऐसे मामलों पर अपनी नाराज़गी जता चुका है। अवैध निर्माणों के बिजली, पानी के कनैक्शन काटने के आदेश दिये गये थे। उस समय प्रदेश भर में 35000 से भी अधिक ऐसे निर्माण सामने आये थे जिनमें नक्शे पास करवाना तो दूर बल्कि नक्शे संवद्ध प्रशासन को सौंपे ही नहीं गये थे। प्रदेश में अवैध निर्माणों और वनभूमि पर अवैध कब्जों के मामले अदालत से लेकर एनजीटी तक के संज्ञान में लगातार रहे हैं और इन पर कड़ी कारवाई करने के प्रशासन को निर्देश भी जारी हुए हैं लेकिन परिणाम यह रहा है कि सरकारें इन अवैधताओं को नियमित करने के लिये रिटैन्शन पॉलिसीयां लाती रहीं। जब अदालत ने इसका संज्ञान लिया तो प्लानिंग एक्ट में ही संशोधन कर दिया गया। जब यह संशोधन राज्यपाल के पास पहुंचा और उन्होंने इसे रोक लिया तब भाजपा का एक प्रतिनिधि मण्डल राज्यपाल से मिला तथा संशोधन को स्वीकार करने का आग्रह किया। इस आग्रह के बाद यह संशोधन पारित होकर अधिसूचित हो गया। फिर उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिकाएं आयी और अदालत ने संशोधन को निःरस्त कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले में सरकार के दायित्वों को लेकर जो टिप्पणीयां की हैं उनसे हमारे माननीयों और प्रशासनिक तन्त्र की कार्य प्रणाली पर जो सवाल खड़े हुये हैं वह काफी चौकाने वाले हैं। लेकिन अन्त में यह सब एक रिकार्ड बनकर ही रह गया है। इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। बल्कि जयराम सरकार ने इसी तरह का संशोधन सदन से पारित करवा लिया है।

अब तक की सारी सरकारें इस हमाम में बराबर की नंगी रही हैं। हद तो यह है कि प्रदेश सरकार के प्रशासन द्वारा ही तैयार की गयी रिपोर्ट पर एनजीटी का चर्चित फैसला आधारित है लेकिन वही प्रशासन अपनी ही रिपोर्ट पर अमल नहीं कर पाया है। जब कोई सरकार अवैधताओं और अतिक्रमणों के बोझ से इतनी दब जाये कि वह किसी भी अदालत तथा अपनी ही रिपोर्ट पर अमल करने से बचने के उपाय खोजने लग जाये तो ऐसी आपदाओं में जान और माल की हानि होने से कोई नहीं बचा सकता।

वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 81 से बढ़कर 48 हुई

शिमला। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने पेटेंट, डिजाइन, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के परीक्षण व उन्हें प्रदान करने में हुए सुधारों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारत को एक नवाचार हब के रूप में विकसित करने में अभी लंबा सफर तय करना होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कल मुंबई में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय के कामकाज की समीक्षा की। साथ ही एक मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार बुनियादी ढांचे के निर्माण के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

गोयल ने पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई (जिओग्राफिकल इंडिकेशन) प्रणालियों के इको-सिस्टम को बढ़ावा देने (देश में नवाचार, शोध एवं विकास को प्रोत्साहन देने और भारत की विरासत से जुड़ी नई खोज और ज्ञान को वैश्विक मंच पर लाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2014 से खुद इस क्षेत्र में हो रहे विकास की निगरानी कर रहे हैं। गोयल ने सीजीपीडीटी द्वारा आवेदनों के त्वरित निस्तारण के बारे में बात करते हुए कहा, ''आईपीआर विभाग में लंबित कार्यों में तेजी से कमी आई है। यह भी फैसला लिया गया है कि किसी भी लंबित आवेदन को महीनों में नहीं, दिनों में निस्तारित करना चाहिए।'

गोयल ने देश में स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को सहायता व समर्थन देने के क्रम में विभाग द्वारा शुल्क में कमी का भी उल्लेख किया। स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों के लिए फाइलिंग शुल्क 80 प्रतिशत तक घट गया है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। शुरू से अंत तक हर आवेदन को अब ऑनलाइन प्रोसेस किया जा रहा है, सुनवाई फोन पर हो रही हैं, लोग अब पेटेंट कार्यालय के चक्कर नहीं काटना चाहते हैं।

गोयल ने पूरी प्रक्रिया को ज्यादा आसान बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने जीआई टैग और उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने बौद्धिक संपदा कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था के साथ ही पेटेंट जांच प्रक्रिया में सहायता के लिए अंशकालिक आधार पर प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षकों को जोड़ने पर विचार करने के लिए भी कहा है।

सीजीपीडीटी के अधिकारियों ने आईपी प्रक्रिया के सरलीकरण और पहले की तुलना में व्यवस्थित करने व फाइलिंग व सेवाओं को सुगम बनाने को प्रोत्साहन देने के लिए निस्तारण की नई समयसीमा और डिजिटल मोड पर स्थानांतरण सहित पूरी प्रक्रिया में बदलाव के बारे में भी बताया। उदाहरण के लिए, ट्रेड मार्क नियमों के तहत 74 प्रपत्रों के स्थान पर 8 समेकित प्रपत्र लागू कर दिए गए हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि विशेष रूप से स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों आदि द्वारा जमा आवेदनों के लिए पेटेंट की जांच में तेजी लाई जा रही है। उठाए गए कदमों के प्रभाव के आकलन में यह देखने में आया है कि ई-फाइलिंग 30 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है।

भारत में पिछले 5-6 साल में पेटेंट, कॉपीराइट में तेज बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। पेटेंट आवंटनों की संख्या 2015-16 के 6,326 से बढ़कर 2020-21 में 28,391 हो गई, जबकि ट्रेड मार्क्स पंजीकरणों की संख्या 2015-16 के 65,045 से बढ़कर 2020-21 में 2,55,993 हो गई। इसी प्रकार, 2015-16 में 4,505 कॉपीराइट दिए गए थे, वहीं पिछले वित्त वर्ष में 16,402 कॉपीराइट दिए गए थे।

इन घटनाक्रमों से वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार देखने को मिला। भारत 2020 में इस सूचकांक में 33 पायदान चढ़कर 48वें पायदान पर पहुंच गया, जबकि 2015-16 में यह 81वें पायदान पर था।

पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय के बारे में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) कार्यालय मुंबई में स्थित है। यह उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।

महानियंत्रक पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000 और ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 के कामकाज की निगरानी करते हैं। साथ ही इन विषयों से जुड़े मसलों पर सरकार को परामर्श देते हैं।

'पेटेंट कार्यालय' का मुख्यालय कोलकाता में है, 'ट्रेड मार्क रजिस्ट्री' मुंबई में है और 'जीआई रजिस्ट्री' चेन्नई में है। 'पेटेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम' (पीआईएस) और 'नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट' (एनआईआईपीएम) के कार्यालय नागपुर में हैं।

बागवानी फसलों के लिए नई पॉलीहाउस प्रौद्योगिकी

शिमला। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर- सीएमईआरआई), दुर्गापुर के निदेशक डॉ. (प्रो.) हरीश हिरानी ने पंजाब के लुधियाना में (नेचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस फैसिलिटी' का उद्घाटन किया और 'रिट्रैक्टेबल रूफ पॉलीहाउस) की आधारशिला रखी।

प्रोफेसर हिरानी ने प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि

किसानों को अत्यधिक या अपर्याप्त ठंड, गर्मी, बारिश, हवा, और अपर्याप्त वाष्पोत्सर्जन से जुड़े अन्य कारकों जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और साथ ही भारत में कीटों के कारण भी वर्तमान में लगभग 15 प्रतिशत फसल का नुकसान होता है तथा यह नुकसान बढ़ सकता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन कीटों के खिलाफ पौधों की रक्षा प्रणाली को कम करता है। पारंपरिक पॉलीहाउस से कुछ हद तक इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। पारंपरिक पॉलीहाउस में मौसम की विसंगतियों और कीटों के प्रभाव को कम करने के लिए एक स्थिर छत होती है। हालांकि, छत को ढंकने के अब भी नुकसान हैं जो कभी-कभी अत्यधिक गर्मी और अपर्याप्त प्रकाश (सुबह-सुबह) का कारण बनते हैं। इसके अलावा, वे कार्बन डाईऑक्साइड, वाष्पोत्सर्जन और जल तनाव के अपर्याप्त स्तर के लिहाज से भी संवेदनशील होते हैं। खुले क्षेत्र की स्थितियों और पारंपरिक पॉलीहाउस स्थितियों का संयोजन भविष्य में जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिहाज से एक ज्यादा बेहतर तरीका है।

डॉ. हरीश हिरानी ने यह भी बताया कि केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमईआरआई) एक्सटेंशन सेंटर लुधियाना में एक ''रिट्रैक्टेबल रूफ पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी'' स्थापित कर रहा है। हर मौसम में काम करने लिहाज से उपयुक्त इस प्रतिष्ठान में ऑटोमैटिक रिट्रैक्टेबल रूफ (स्वचालित रूप से खुलने-बंद होने वाली छत) होगा जो पीएलसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कंडीशनल डेटाबेस से मौसम की स्थिति और फसल की जरूरतों के आधार पर संचालित होगा। इस प्रौद्योगिकी से किसानों को मौसमी और गैर-मौसम वाली दोनों ही तरह की फसलों की खेती करने में मदद मिलेगी। यह पारंपरिक खुले मैदानी सुरंगों और प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस की तुलना में इष्टतम इनडोर सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों का निर्माण करके उच्च उपज, मजबूत और उच्च शेल्फ-लाइफ उपज प्राप्त कर सकता है, और साथ ही यह जैविक खेती के लिए व्यवहार्य प्रौद्योगिकी भी है।

इस प्रौद्योगिकी के विकास में लगे अनुसंधान दल का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक जगदीश माणिकराव ने बताया कि रिट्रैक्टेबल रूफ का उपयोग सूर्य के प्रकाश की मात्रा, गुणवत्ता एवं अवधि, जल तनाव, आर्द्रता, कार्बन डाई-ऑक्साइड और फसल एवं मिट्टी के तापमान के स्तर को बदलने के लिए किया जाएगा। वही फार्म मशीनरी एंड प्रिसिजन एग्रीकल्चर के प्रमुख और वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप राजन ने बताया कि यह प्रतिष्ठान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईएचबीटी), पालमपुर के सहयोग से विकसित किया जा रहा है और फसल के आधार पर पॉलीहाउस को स्वचालित करने में ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने की प्रक्रिया में है। यह मौसम की जरूरतों और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) पर आधारित होगा तथा सक्षम किसान अनुकूल यूजर इंटरफेस प्रदान करेगा।

निदेशक ने यह भी बताया कि चूंकि नई पॉलीहाउस प्रणाली के लाभों पर वैज्ञानिक प्रयोगात्मक आंकड़े की कमी है, इसलिए फसल उत्पादन और उपज की गुणवत्ता की तुलना करने के लिए प्राकृतिक रूप से हवादार पॉलीहाउस और रिट्रैक्टेबल रूफ पॉली हाउस दोनों में बागवानी फसलों की खेती की जाएगी। उन्होंने कहा कि नैचुरली वेंटिलेटेड पॉलीहाउस और रिट्रैक्टेबल रूफ पॉलीहाउस को साथ-साथ स्थापित करके, हम जरूरी वैज्ञानिक आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं और परिणामों का विश्लेषण करके उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। इस प्रतिष्ठान का उपयोग किसानों के लिए एक प्रदर्शनी खेत के रूप में किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण

शिमला। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में चरित्र निर्माण, मानवीय मूल्यों का विकास, आध्यात्मिक नींव के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करना, अनिश्चित भविष्य का मुकाबला करने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण करना तथा गरिमा, आत्मसम्मान एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना है। भारत की शिक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है ताकि हमारे युवा उपरोक्त गुणों को आत्मसात कर सकें। सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए युवाओं में विश्वस्तरीय दक्षता का विकास हो सके तथा देश को भौगोलिक लाभांश का फायदा मिल सके। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के लिए अच्छे गुणों को विकसित करने के साथ व्यक्ति को प्रशिक्षण प्रदान कर सके। इसके अलावा मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्यक्ति में पूरी दुनिया के लोगों के प्रति बन्धुत्व की भावना तथा अन्य गुणों का विकास हो सके। इस संदर्भ को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) में सभी आवश्यक बदलावों को शामिल करने की कोशिश की गई है तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक वर्ष पहले भारत सरकार द्वारा घोषित इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना और भी जरूरी हो गया है। एनईपी-2020 वास्तव में सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए राष्ट्र निर्माण के प्रति भारत सरकार की कटिबद्धता को दर्शाता है।

विद्यार्थी केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में ऐसी ठोस व्यवस्था की गई है जिससे समानता, किफायती और सीखने के व्यापक अवसरों के आधार पर आजीवन सीखने वाले ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना संभव हो सकेगा। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करके विविध पाठयक्रमों एवं संस्थानों को चुनने में सक्षम बनाएगा और इसके साथ ही किसी कार्यक्रम या पाठयक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक क्रेडिट को अर्जित और संग्रहीत करके उन्हें संबंधित डिग्री प्रदान करने को सुविधाजनक बनाएगा। विद्यार्थियों को किसी कार्यक्रम या पाठयक्रम को छोड़ दूसरे कार्यक्रम या पाठयक्रम में प्रवेश लेने या उससे बाहर निकलने के विकल्प का उपयोग एक से अधिक बार करने की इजाजत दिए जाने से शिक्षार्थियों के विविध समूह की सीखने की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना संभव हो सकेगा। कौशल विकास करने के मजबूत घटकों से युक्त बहु-विषयक पाठयक्रम संरचना से विद्यार्थियों को खंडित एवं गैर-प्रासंगिक शिक्षण परिवेश के बजाय प्रासंगिक और समग्र शिक्षण परिवेश से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। ज्ञान सीखने की विधि को रोचक बनाने, और उच्च स्तर की चिंतन क्षमताओं को विकसित करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण अध्यापन, अर्थात, चर्चा/ बहस/ वाद-विवाद, प्रदर्शन, गतिविधि, परियोजना/शोध निबंध/ इंटर्नशिप/केस स्टडी और भ्रमण आधारित सहयोगात्मक शिक्षण, और मिश्रित अध्यापन दृष्टिकोण के अनुरूप एवं अन्य तरीकों पर विशेष जोर दिया गया है। स्नातक संबंधी विशिष्ट गुण (जीए)/शिक्षण संबंधी विशिष्ट उपलब्धियां विद्यार्थियों में उन गुणों, कौशल और गहन समझ को सुनिश्चित करेंगी जिसे डिग्री प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अध्ययन करते समय विद्यार्थियों में विकसित करने की आवश्यकता होती है। ये विशिष्टताएं पाठयपुस्तकों और कक्षाओं के दायरे से परे दक्षताओं को विद्यार्थियों में विकसित करने में मदद करेंगी। यही नहीं, ये विशिष्टताएं स्नातकों को वैश्वीकृत नागरिक बनने के साथ-साथ राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक हालात को बेहतर करने में सक्षम 'ज्ञान आधारित समाज' का प्रभावशाली सदस्य बनने के लिए भी सशक्त बनाएंगी। इस नीति में विद्यार्थियों की शिक्षण संबंधी सटीक उपलब्धियों या परिणामों को मापने के लिए उनका आकलन करने के उपयुक्त साधनों को विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। भारतीय भाषाओं के बीच ज्ञान साझा करने के लिए परिकल्पित राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के जरिए गवर्नेंस एवं नीति संबंधी ज्ञान के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं में संरक्षित पारंपरिक ज्ञान को प्रमुख भारतीय भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे निश्चित रूप से देशवासियों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने को काफी प्रोत्घ्साहन मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में सुझाये गये परिवर्तनकारी सुधार प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना लागू नहीं किए जा सकते। सिखाने -सीखने की प्रक्रिया में शिक्षकों और छात्रों को समान रूप से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। बहु-विषयक शिक्षा के युग की शुरुआत करने के लिए, एक व्यापक सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव की जरूरत है। शैक्षणिक समुदाय, उद्योग जगत और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के प्रयोगशालाओं के बीच बेहतर पारस्परिक आदान-प्रदान जरूरी है। 'वोकल फॉर लोकल' की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए शोध के संस्थागत जोर वाले पहलू अब सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और स्थानीय एवं क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप होंगे।

ये सभी कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को उद्यम संबंधी और चुस्त सोच, परिस्थितियों के अनुरूप ढलने वाली नेतृत्व शैली, लचीला, पारस्परिक संवाद कौशल, व्यापक सोच, समस्या के समाधान की क्षमता, डिजिटल निपुणता और वैश्विक संचालन कौशल विकसित करने और वास्तविक जीवन के परिदृश्यों के अनुकूल बनाने में पर्याप्त रूप से सक्षम बनाते हैं क्योंकि ये कदम क्या सीखना है के बजाय वास्तविक रूप से जीवन भर सीखने और सीखने के तरीके पर जोर देते हैं, जोकि वर्तमान वैश्वीकृत वातावरण में सीखने से संबंधित एक आवश्यक गुण हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को हकीकत में बदलने के लिए एक सख्त लेकिन हल्की, गतिशील एवं लचीली नियामक व्यवस्था और सुविधाजनक समग्र कार्यान्वयन योजना समय की मांग है। प्रधानमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय कार्यशालाओं के कई दौर के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों तक पहुंचाने के लिए वास्तव में दिन-रात एक कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बहु-विषयक और समग्र शिक्षा(उच्च शिक्षा में समानता और समावेशन(शोध, नवाचार एवं रैंकिंग(उच्च शिक्षा की वैश्विक पहुंच(एक प्रेरक, सक्रिय एवं सक्षम संकाय(एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली(प्रशासन एवं विनियमन(भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषाओं, संस्कृति एवं मूल्यों को प्रोत्साहन(और प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण जैसे इस नीति के नौ प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। मेरा यह स्पष्ट विचार है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का समय आ गया है।

-राघवेन्द्र पी. तिवारी-
कुलपति, पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भठिंडा

मेरी राय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से बहु-विषयक सीखने के नतीजों पर आधारित पाठयक्रम और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को लागू करना संभव है। हालांकि, कोरोना महामारी के कारण इसका कार्यान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, शिक्षकों को शिक्षा के उभरते हुए विमर्श में ढलने और इसे अपनाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए। उन्हें पाठयक्रम की विषय-वस्तु को नए और ताज़ा विचारों से भरने में सक्षम होना चाहिए, उन्हें कक्षा की पढ़ाई से इतर शिक्षार्थियों को पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए, उन्हें शिक्षा के सभी पहलुओं से संबंधित सार्थक विमर्शों में शामिल करना चाहिए और समाधान खोजने में उनकी मदद करनी चाहिए। शिक्षकों को व्यक्तिगत/ साहसी/सहकारी/सहयोगी/ सेवारूपी /स्थित/चयन की स्वतंत्रता वाली, प्रासंगिक, एकीकृत व चिंतनशील और व्यवहार उन्मुख शिक्षण शैली का सहारा लेते हुए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की जड़ता को समाप्त करते हुए एक गतिशील शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इसका सफल कार्यान्वयन शिक्षा-प्रशासकों, छात्र-समुदाय, माता-पिता, नागरिक समाज और मीडिया के सहयोग पर भी निर्भर करता है।

संक्षेप में कहें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 सहायक, देखभाल करने वाली व भरोसेमंद है और इसका उद्देश्य मानवता की भलाई और शैक्षणिक व नैतिक उत्कृष्टता के बीच संबंध विकसित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 राष्ट्रीय आकांक्षाओं को साकार करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। अगर एक साल के घुटनों पर चलने वाले बच्चे को भी सही संदर्भों और सही इरादे से युवा होने तक पोषण दिया जाए, तो इसमें निहित परिवर्तनकारी सुधार ऐसे भारत केंद्रित युवाओं को तैयार करेंगे जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा हासिल करने और भारत को विश्व गुरु के रूप में दोबारा स्थापित करने में सक्षम होंगे। आइए हम एक बदले हुए लर्निंग इको-सिस्टम के जरिए प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' को बनाने के आहवान पर आगे बढ़ें।

यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं।

जनसमर्थन से हो जनसंख्या नियंत्रण

भारत के पास भूमि कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है। कल्पना कीजिए कि जब भारत यूएन की रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ चीन को पछाड़ कर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा तो क्या स्थिति होगी।

-डॉ नीलम महेंद्र-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने के फैसले ने इस विषय को राजनैतिक गलियारों में चर्चा से लेकर आम लोगों के बीच सामाजिक विमर्श का केंद्र बना दिया है। राजनैतिक दल और अन्य संगठन अपने अपने वोटबैंक और राजनैतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर इसका विरोध अथवा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर राजनीति से इतर बात की जाए तो यह विषय अत्यंत गम्भीर है जिसे वोटबैंक की राजनीति ने संवेदनशील भी बना दिया है।

दरअसल आज भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरे स्थान पर आता है और यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनकर इस सूची में पहले स्थान पर आ जाएगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जनसंख्या के विषय में पहले स्थान पर आने वाले भारत के पास इतने संसाधन और इतनी जगह है जिससे यह भारतमूमि अपने सपूतों को एक सम्मान एवं सुविधाजनक जीवन दे सके? तो आइए इसे कुछ आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। भारत के पास विश्व की कुल भूमि क्षेत्र का मात्र 2.4 प्रतिशत है जबकि भारत की आबादी दुनिया की कुल आबादी का 16.7 प्रतिशत है। यहाँ यह बता दिया जाए कि विश्व के डेवलप्ड यानी विकसित देशों की सामूहिक जनसंख्या 17 प्रतिशत के आसपास है और अकेले भारत की जनसंख्या 16.7 प्रतिशत। इस विषय का इससे भी अधिक चिंताजनक पहलू यह है कि भारत के एक राज्य की जनसंख्या की तुलना कई देशों की कुल जनसंख्या से की जा सकती है। जैसे उत्तरप्रदेश की जनसंख्या ब्राजील, महाराष्ट्र की मेक्सिको, बिहार की फिलीपींस, पश्चिम बंगाल की वियतनाम, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु की तुर्की, कर्नाटक की इटली के बराबर आदि।

यह आंकड़े बता रहे हैं कि स्तिथि कितना गंभीर रूप ले चुकी है। ऐसे ही कुछ और दिलचस्प आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस जनसंख्या के मामले में नौंवे स्थान पर है। और जो चीन जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आता है वो चीन क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में चौथे स्थान पर आता है जबकि भारत आठवें स्थान पर। यानी भारत के पास भूमि कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा है। कल्पना कीजिए कि जब भारत यूएन की रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ चीन को पछाड़ कर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा तो क्या स्थिति होगी। क्या इन परिस्थितियों में कोई भी देश गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़कर अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की कल्पना भी कर सकता है? लेकिन इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस देश की राजनीति उस मोड़ पर पहुंच गई है जहाँ हर विषय वोटबैंक से शुरू हो कर वोटबैंक पर ही खत्म हो जाता है। खेती किसानी हो या फिर शिक्षा स्वास्थ्य अथवा जनसंख्या जैसे मूलभूत विषय ही क्यों न हो सभी को वोटबैंक की राजनीति से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे राजनेता अपने राजनैतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच ही नहीं पाते। विगत कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि सत्ता धारी दल अगर किसी समस्या का समाधान खोजने के प्रयास में कोई कानून या नीति लेकर आता है तो विपक्ष उसके विरोध में उतर आता है। इस समय देश वाकई में अजीब दौर से गुज़र रहा है जहाँ समस्या से अधिक विकट देश के मौजूदा हालात हो गए हैं। क्योंकि एक तरफ देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाना वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक प्रतीत हो रहा है तो दूसरी तरफ इस विषय का राजनीतिकरण कर बड़े पैमाने पर इसका विरोध होने की आशंका भी बनी हुई है। इसलिए जनसंख्या से संबंधित कोई भी कानून बनाने से पहले आवश्यक है कि इस विषय में जन जागरूकता लाई जाए। इससे लोग बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों और सीमित परिवार के फायदों से परिचित ही नहीं होंगे बल्कि इस विषय में दुष्प्रचार से भ्रमित होने से भी बचेंगे। हालांकि उत्तरप्रदेश सरकार की प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति में जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सोचा गया है। इसलिए प्रस्तावित नीति में परिवार नियोजन करने वाले परिवारों को सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं तो अधिक बच्चों वाले परिवारों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन इस विषय को लेकर राजनैतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। उत्तरप्रदेश के उलट अगर भारत के ही राज्य केरल का उदाहरण लिया जाए तो केरल में सबसे कम सकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर होने के साथ साथ उच्चतम जीवन प्रत्याशा और उच्चतम लिंगानुपात है। यानी जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रण में है, लोगों का जीवन स्तर बेहतरी की ओर अग्रसर है और लड़का लड़की का अनुपात भी देश में सबसे अधिक है। गौरतलब है कि केरल केवल जनसंख्या के मामले में ही बेहतर नहीं है वो साक्षरता के मामले में भी सबसे अधिक साक्षरता दर के साथ भारत का अग्रणी राज्य है। जबकि उत्तरप्रदेश ना सिर्फ जनसंख्या के मामले में 29 वें पायदान पर आता है बल्कि लिंगानुपात में भी 26 वें पायदान पर आता है। यहाँ यह बता दिया जाए कि केरल में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम यह समझें कि जनसंख्या को कानून से ही नियंत्रित किया जा सकता है तो ऐसा नहीं है। कानून अपने आप में अपर्याप्त रहेगा जब तक लोग उसे स्वेच्छा से स्वीकार न करना चाहें। इसलिए सरकार चाहे किसी राज्य की हो या केंद्र की जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय पर जल्दबाजी में कानून लाकर जनसंख्या को कितना नियंत्रित कर पाएगी यह तो समय बताएगा लेकिन बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा जरूर दे देगी।

जैसे हमने प्लास्टिक को कानूनी तौर पर बैन करने से पहले से देश में प्लास्टिक मुक्ति को जन आंदोलन बनाया, देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता को भी जन आंदोलन बनाकर उसमें जन जन की भागीदारी सुनिश्चित की उसी प्रकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून के साथ साथ जनजागरूकता के लिए विभिन्न अभियान चलाए ताकि लोग स्वेच्छा से इसमें भागीदार बनें और विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। जम्मू कश्मीर इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। चूँकि वहाँ के लोग जागरूक हो चुके थे इसलिए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के समय विपक्षी दलों के विरोध को जनता का समर्थन नहीं मिला। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनावों में भी स्थानीय लोगों ने राजनैतिक स्वार्थ से प्रेरित गुपकार गठबंधन को नकार दिया था। इसलिए जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों और सीमित परिवार के फायदों के प्रति अगर लोग जागरूक होंगे तो कोई दल कोई संगठन वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। अत: वर्तमान परिस्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून जितना जरूरी है उतना ही जनसमर्थन भी जरूरी है जो जनजागरण से ही संभव है।

हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीआरओ ने बचाव एवं राहत कार्य का संचालन किया

विभिन्न स्थलों पर भूस्खलन को हटाने के लिए बीआरओ अपने कर्मियों और उपकरणों की तैनाती करता है

मनाली-सरचू सड़क यातायात फिर से बहाल किया गया

बीआरओ की टीमों ने फंसे हुए लोगों को बचाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया

कार्य संचालन के दौरान, दो बीआरओ कर्मियों ने जान गँवाई

शिमला। सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के दौरान बचाव और राहत अभियान का संचालन कर रहा है। लाहौल और स्पीति घाटी में, रणनीतिक मनाली-सरचू मार्ग को कई स्थानों पर भूस्खलनों के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। शिमला स्थित बीआरओ की परियोजना दीपक

ने बचाव और राहत अभियान को संचालित करने और क्षतिग्रस्त सड़क को साफ करने के कार्यों को अंजाम देने के लिए कर्मियों और उपकरणों के साथ अपने प्रशिक्षित अभियंता कार्यबल को शीघ्र इस स्थल पर भेजा।

29 जुलाई, 2021 को मनाली-लेह मार्ग पर बारालाचला दर्रे के आगे सरचू के पास ऐसे ही एक हिस्से पर, महिलाओं और बच्चों सहित कई लोग फंसे हुए थे और इस क्षेत्र के अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे। बीआरओ टीम ने 14,480 फीट की ऊंचाई पर स्थित केनलुंग सराय के पास अन्य भूस्खलनों की एक श्रृंखला से अवरूद्ध हुए मार्ग को साफ करते हुए लोगों को बचाया। हालांकि, बचाव प्रयासों में शामिल दीपक प्रोजेक्ट के नायक रीतेश कुमार पाल ने अपने प्राण गँवा दिए। बाद में सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया।

27 जुलाई, 2021 को एक अन्य घटना में, भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध किलर-टांडी सड़क मार्ग को खोलने के लिए बीआरओ के एक अलग अभियंता कार्य बल को तैनात किया गया था। क्षेत्र में दो यात्री वाहन फंसे हुए थे। पहले से ही इस मार्ग में दो भूस्खलनों को साफ करने वाले इस दल ने फिसलन भरे इस इलाके में फसे नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए देर रात तक निकासी अभियान चलाया। कार्य संचालन के दौरान, टीम के कुछ सदस्य, छह नागरिक और एक नागरिक वाहन अचानक आई बाढ़ में बह गए। घटना में कनिष्ठ अभियंता राहुल कुमार की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य को बीआरओ कर्मियों ने बचा लिया।

बाद में बीआरओ कर्मियों ने भूस्खलन से अवरूद्ध हुए मार्ग को साफ किया, फंसे हुए यात्रियों को बचाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

देश में 5 लाख लोगों के इलाज के लिए 70000 आईसीयू बैड उपलब्धः डा. मनविंदरजीत कौर

शिमला/शैल। ग्रेशियन सुपर स्पैशलिटी अस्पताल मोहाली की टीम ने आईसीयू की सुविधा तथा गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक सेमीनार में गंभीर मरीजों की संभाल, कोविड केयर तथा वेंटीलेशन

संबंधी बहुत सारे तथ्यों तथा भ्रमों के बारे में चर्चा की।

ग्रेशियन अस्पताल में फेफड़ों के रोगों के माहिर तथा क्रिटिकल केयर के सीनियर कंस्लटेंट डा. प्रीती शर्मा ने कहा कि क्रिटिकल तथा इंटेसिल केयर में मरीज की गंभीर हालत के समय उसकी जिंदगी बचाने का प्रबंध शामिल है, जिसमें अकसर जीवन रक्षक प्रणाली की जरूरत पड़ती है।

ऐसी जीवन रक्षक प्रणाली की सुविधा एक अच्छे अस्पताल में ही दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि आईसीयू में 24 घंटे डाक्टर तथा नर्सें तैनात रहते हैं। डाक्टरी स्टाफ के अलावा हर तरह की अति-आधुनिक टेक्नोलॉजी, वेंटीलेटर, डायलसिस मशीनें, इको, हाई-फ्लो, नेजल केनला, कार्डियक मॉनीटर शामिल होते हैं।

डा. प्रीती शर्मा ने बताया कि कोविड 19 की दूसरी लहर दौरान ग्रेशियन अस्पताल में गंभीर बीमारियों से पीड़ित 600 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें चंडीगढ़ ट्राईसिटी के अलावा दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, मेरठ, जम्मू, बरेली, देहरादून, हरिद्वार तथा मथुरा के मरीज भी शामिल थे।

डा. प्रीती शर्मा ने बताया कि हमारे देश में 10 हजार लोगों के पीछे 7 डाक्टर हैं, जो कि औसतन आधे हैं। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 50000 क्रिटिकल केयर डाक्टरों की जरूरत है, जबकि हमारे देश में सिर्फ 8350 ऐसे डाक्टर हैं।

ग्रेशियन अस्पताल मोहाली के क्रिटिकल केयर के प्रमुख तथा सीनियर कंस्लटेंट डा. मनिंदरजीत कौर ने बताया कि लगभग सभी बड़े प्राइवेट तथा सरकारी अस्पतालों में इंटेसिव केयर यूनिट कायम किए हुए हैं। जो ध्यान से देखा जाए तो 10-20 बिस्तरों वाले यह क्रिटिकल केयर यूनिट अकसर मरीजों से भरे रहते हैं।

सडक् हादसों या अन्य दुर्घटनाओं का शिकार मरीजों को इन यूनिटों में दाखिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि देश भर में सिर्फ 70 हजार आईसीयू बैड उपलब्ध हैं। आबादी के इलाज के साथ यहां 5 लाख आईसीयू बैडों की जरूरत है।

फेफड़ों तथा छाती के रोगों के माहिर डाक्टर हितेश गौड़ ने कहा कि भारत में अभी भी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है। हमारे देश में 10000 लोगों के पीछे सिर्फ 10 अस्पताल बैड उपलब्ध हैं, जबकि विश्व में औसतन 10000 लोगों के पीछे 30 बैड हैं। उन्होंने बताया कि इस कमी को पूरा करने के लिए सभी अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों में कम से कम 10 प्रतिशत आइसीयू बैड होने चाहिए।

सरकार फिट इंडिया को एक जन आंदोलन बना रही हैः अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। खेल मंत्रालय फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न हितधारकों के सहयोग से विभिन्न गतिविधियों और अभियानों के माध्यम से फिटनेस के बारे में सक्रिय रूप से जागरूकता फैला रहा है। फिट इंडिया बैनर के तहत मंत्रालय की शुरू की गई प्रमुख गतिविधियों में ऑनलाइन/ ऑफलाइन गतिविधियां शामिल हैं। इनमें प्लॉग रन, विद्यालय प्रमाणन प्रणाली, युवा क्लब प्रमाणन प्रणाली, स्कूल वीक सेलिब्रेशन्स, साइक्लोथॉन, योग दिवस उत्सव, फ्रीडम रन, लॉकडाउन के दौरान सक्रिय दिवस श्रृंखला, चैंपियन टॉक्स, डायलॉग श्रृंखला, स्वदेशी खेल श्रृंखला, फिट इंडिया विषय क्षेत्र संबंधीअभियान और प्रभात फेरी हैं। इसके अलावा विभिन्न आयु समूहों के लिए फिट इंडिया आयु-उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल भी जारी किए गए हैं।

यह मंत्रालय फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत के बाद सक्रिय रूप से फिटनेस के बारे में जागरूकता फैला रहा है, जिसमें ऐसी साधारण शारीरिक गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया, जो हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आयोजित सभी कार्यक्रमों/गतिविधियों में भागीदारी के लिए कारोबारियों को आमंत्रित किया जा रहा है और फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया साइक्लोथॉन आदि जैसे आयोजनों में उनकी सहभागिता काफी उत्साहजनक रही है।

फिट इंडिया को एक जन आंदोलन बनाने में केंद्र सरकार की भूमिका उत्प्रेरक की है और इस कार्यक्रम के लिए अलग से कोइ निधि आवंटित नहीं की गई है।

यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र में केंद्र सरकार को 49.24 करोड़ के प्रस्ताव प्रस्तुत

शिमला/शैल। केंद्र प्रायोजित योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य के मत्स्य विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 49 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह मत्स्य पालन क्षेत्र को अधिक प्रभावी और जीवंत तरीके से विकसित करने के लिए विभाग की पहल को बढ़ाएगा।

यह जानकारी पीआईबी को सतपाल मेहता, निदेशक, मत्स्य विभाग द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि राज्य में मछलियों के प्रभावी प्राकृतिक प्रजनन के लिए सभी जलाशयों, नदियों और नालों में निकट सीजन को सख्ती से लागू किया जा रहा है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं जैसे मछली उत्पादन, बीज उत्पादन गतिविधियों/ निर्माण कार्यों के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सात तरह के कोरोना वायरस करते हैं इंसानों को प्रभावितः डायरेक्टर एम्स

शिमला/शैल। एसोचैम ने डॉ गुलेरिया के साथ बातचीत सत्र का आयोजन किया। इसमें कोविड -19 के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, एसोचैम ने प्रमुख पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ रणदीप गुलेरिया के साथ बातचीत की।

इस बातचीत के दौरान एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने बताया कि कोविड-19 वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, लेकिन यह अन्य सभी अंगों को भी प्रभावित कर सकता है।

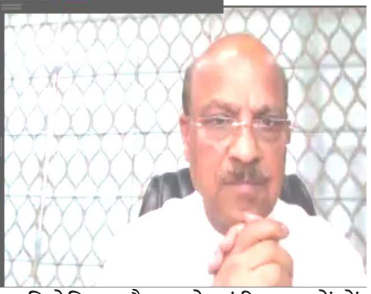

डॉ गुलेरिया ने साझा किया कि सात तरह के कोरोना वायरस हैं जो मनुष्यों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से चार सर्दी, खांसी, बुखार जैसे हल्के लक्षण पैदा करते हैं जबकि अन्य तीन फेफड़ों में गंभीर प्रभाव डालते हैं।

उन्होंने कहा, जो रोगी बुजुर्ग हैं, लंबे समय तक आईसीयू में रहे, उन्हें मकैनिकल वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है, धूम्रपान करने वालों या पुरानी शराब के कारण फेफड़ों को दीर्घकालिक नुकसान होने की संभावना अधिक होती है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार एक प्रमुख कुंजी है। पोस्ट कोविड रोगियों को भी सतर्क रहना चाहिए और 3 पी यानी प्लेनिंग पेसिंग और प्रियोटीटाइजेशन को याद रखना चाहिए।

डॉ गुलेरिया ने सत्र के दौरान उपस्थित लोगों द्वारा उठाए गए कई सवालों के जवाब भी दिए और उनकी शंकाओं का समाधान किया।

एसोचैम हिमाचल प्रदेश स्टेट डवलपमेंट काऊंसिल के चेयरमेन जितेंद्र सोढी, ने अपने संबोधन के दौरान कहा, यह सर्वविदित है कि कोविड-19 फेफड़ों की जटिलताओं जैसे निमोनिया और सबसे गंभीर मामलों में, एक्यूट रिस्पायरेट्री डिस्ट्रिज सिंड्रोम (एआरडीएस) आदि का कारण बन सकता है। मधुमेह, हृदय रोग से पीड़ित लोगों की स्थिति और खराब हो सकती है। इसलिए उन्हें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।

डॉ गुलेरिया ने भारत में तीसरी लहर और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की उपलब्धता और आवश्यकता को पूरा करने और तीसरी लहर को कम करने के लिए देश की तैयारी के बारे में भी उल्लेख किया, जो इतनी गंभीर नहीं होगी।

भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को बाघों के बेहतर संरक्षण के लिए वैश्विक सीए/टीएस मान्यता मिली

शिमला। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बाघ संरक्षण वन संरक्षण का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार का दृष्टिकोण लोगों की भागीदारी के साथ वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करके समावेशी बनाने वाला रहा है, जोकि देश की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यादव वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम में बोल रहे थे।

पर्यावरण मंत्री ने 'तेंदुओं, सह-परभक्षियों और शाकभक्षियों की स्थिति-2018' शीर्षक रिपोर्ट भी जारी की। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट इस तथ्य का प्रमाण है कि बाघों के संरक्षण से पूरे इकोसिस्टम का संरक्षण होता है।

वर्ष 2018 में बाघों की संख्या के अखिल भारतीय आकलन के दौरान, देश के बाघों वाले राज्यों में वनाच्छादित प्राकृतिक वासों के भीतर तेंदुओं की आबादी का भी अनुमान लगाया गया था। वर्ष 2018 में भारत के बाघों के विचरण वाले इलाकों में तेंदुओं की कुल आबादी 12,852 (एसई रेंज 12,172 - 13,535) थी। यह 2014 की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि है, जोकि देश के बाघों वाले 18 राज्यों के वनाच्छादित प्राकृतिक वासों में 7,910 (एसई 6,566-9,181) थी।

इस कार्यक्रम में भारत के उन 14 बाघ अभयारण्यों के बारे में चर्चा की गई, जिन्हें ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड-टाइगर स्टैंडर्ड्स (सीएढ़टीएस) की मान्यता मिली है। जिन 14 बाघ अभयारण्यों को मान्यता दी गई है उनमें असम के मानस, काजीरंगा और ओरंग, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, महाराष्ट्र के पेंच, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश के दुधवा, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, केरल में परम्बिकुलम, कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व और तमिलनाडु के मुदुमलई और अनामलई टाइगर रिजर्व शामिल हैं।

कंजर्वेशन एश्योर्ड-टाइगर स्टैंडर्ड्स को टाइगर रेंज कंट्रीज के वैश्विक गठबंधन द्वारा मान्यता संबंधी उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे बाघों एवं संरक्षित क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। आधिकारिक तौर पर 2013 में लॉन्च किया गया यह मानक लक्षित प्रजातियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है और प्रासंगिक संरक्षित क्षेत्रों में इन मानकों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है। सीए-टीएस विभिन्न मानदंडों का एक सेट है, जो बाघ से जुड़े स्थलों को इस बात को जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा।

इस कार्यक्रम में पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी भाग लिया। उन्होंने प्रकृति और जीवन के सभी रूपों के साथ सामंजस्य बिठाने की सदियों पुरानी परंपरा पर जोर दिया और कहा कि एक शीर्ष शिकारी के रूप में बाघ स्वस्थ इकोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी से एक साथ आने और हमारे बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों को बचाने के लिए साथ आने का आह्वान किया।

दोनों मंत्रियों की उपस्थिति में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने बाघों और जंगलों की सुरक्षा में लगे अग्रिम पंक्ति के कुछ वन्यकर्मियों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए उन्हें 'बाघरक्षक' के रूप में सम्मानित किया। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा, 'वनों से जुड़े हमारे बल घातक कोविड-19 महामारी के दौरान भी जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा करने के लिए दिन-रात मेहनत करते रहे।' उन्होंने अग्रिम पंक्ति के सभी वन कर्मचारियों को हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा में जुटे रहने की उनकी भावना के लिए बधाई दी।

भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान वन और वन्यजीव संरक्षण को 'आवश्यक सेवाओं' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया। देश के वनों से जुड़े बल कोविड-19 महामारी के दौरान भी जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा में दिन-रात मेहनत करते रहे।

इस कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों, पर्यावरण सचिव आर.पी. गुप्ता और एनटीसीए के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वैश्विक बाघ दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की त्रैमासिक पत्रिका 'स्ट्रिप्स' के एक विशेष संस्करण का विमोचन भी हुआ।

भारत के 40वें स्थल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला

शिमला। कच्छ का रण, गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा से संबंधित भारतीय नामांकन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। भारत ने जनवरी, 2020 में **'धोलावीरा: एक हड़प्पा कालीन नगर से विश्व धरोहर स्थल तक'** शीर्षक से अपना नामांकन जमा किया था। यह स्थल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल था। हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा दक्षिण एशिया में संरक्षित प्रमुख नगर जीवन स्थलों में से एक है और जिसका इतिहास तीसरी शताब्दी ईसा-पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा-पूर्व के मध्य तक का है।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि यह भारत के लिए एक गौरव की बात है कि हमारा देश विश्व धरोहर स्थल की सूची में सुपर 40 के रूप में शामिल हो गया है। इस सफल नामांकन के साथ भारत के पास कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित संपत्ति है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने उन देशों का भी उल्लेख किया जिनके पास 40 या इससे अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें भारत के अलावा अब इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन व फ्रांस शामिल हैं।

धोलावीरा के हड़प्पा नगर के बारे में

धोलावीरा: हड़प्पा संस्कृति का ये नगर, दरअसल दक्षिण एशिया में तीसरी से मध्य-दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व काल की चंद सबसे अच्छे से संरक्षित प्राचीन शहरी बस्तियों में से है। अब तक खोजे गए 1,000 से अधिक हड़प्पा स्थलों में छठा सबसे बड़ा और 1,500 से अधिक वर्षों तक मौजूद रहा धोलावीरा न सिर्फ मानव जाति की इस प्रारंभिक सभ्यता के उत्थान और पतन की पूरी यात्रा का गवाह है बल्कि शहरी नियोजन, निर्माण तकनीक, जल प्रबंधन, सामाजिक शासन और विकास, कला, निर्माण, व्यापार और आस्था प्रणाली के संदर्भ में भी अपनी बहुमुखी उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। अपनी अत्यंत समृद्ध कलाकृतियों के साथ, धोलावीरा की बड़ी अच्छी तरह से संरक्षित ये शहरी बस्ती, अपनी बेहद खास विशेषताओं वाले इस क्षेत्रीय केंद्र की एक जीवंत तस्वीर दर्शाती है जो समग्र रूप से हड़प्पा सभ्यता के मौजूदा ज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

इस पुरातात्विक स्थल के दो भाग हैं: एक दीवार युक्त नगर और दूसरा, नगर के पश्चिम में एक अंत्येष्टि स्थल। चारदीवारी वाले इस नगर में एक प्राचीर युद्ध किला है जिसके साथ प्राचीर वाला अहाता और पूजा-अर्चना का मैदान, और एक सुरक्षित मध्य नगर तथा एक निम्न नगर है। इस किले के पूर्व और दक्षिण में जलाशयों की एक श्रृंखला पाई जाती है। अंत्येष्टि स्थल या श्मशान में अधिकांश अंत्येष्टियां स्मारक रूपी हैं।

धोलावीरा नगर स्वर्णिम दिनों में उसका जो विशिष्ट स्वरूप था वह दरअसल नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धोलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग-अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे जो संभवत: विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों या पेशा और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। जल संचयन प्रणालियों, जल निकासी प्रणालियों के साथ-साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री के

डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आमतौर पर नदियों और जल के बारहमासी स्रोतों के पास स्थित रहने वाले हड़प्पा के अन्य पूर्ववर्ती शहरों के विपरीत खादिर द्वीप में धोलावीरा ऐसे स्थान पर अवस्थित था जो खनिज और कच्चे माल (तांबा, सीप, गोमेद-कार्नीलियन, स्टीटाइट, सीसा, धारियों वाले चूना पत्थर, इत्यादि) के विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करने और इसके साथ ही मगन (आधुनिक ओमान प्रायद्वीप) एवं मेसोपोटामिया क्षेत्रों में आंतरिक और बाह्य व्यापार को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से अत्यंत रणनीतिक था।

धोलावीरा दरअसल हड़प्पा सभ्यता(शुरुआती, परिपक्व और इसके बाद के हड़प्पा दौर वाले) से संबंधित एक आद्य-ऐतिहासिक कांस्य युग वाली शहरी बस्ती का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और वहां तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान एक बहु-सांस्कृतिक एवं वर्गीकृत समाज होने के अनेक प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक हड़प्पा चरण के दौरान 3000 ईसा पूर्व के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं। यह नगर लगभग 1,500 वर्षों तक खूब फला-फूला जिससे वहां काफी लंबे समय तक लोगों के निरंतर निवास करने के संकेत मिलते हैं। यहां पर उत्खनन के जो अवशेष हैं वे स्पष्ट रूप से बस्ती की उत्पत्ति, उसके विकास, चरम पर पहुंचने और फिर बाद में उसके पतन का संकेत देते हैं जो इस नगर के स्वरूप एवं स्थापत्य तत्वों या घटकों में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ विभिन्न अन्य विशेषताओं में स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होते हैं। धोलावीरा अपनी पूर्व नियोजित नगर योजना, बहु-स्तरीय किलेबंदी, परिष्कृत जलाशयों और जल निकासी प्रणाली, और निर्माण सामग्री के रूप में पत्थर के व्यापक उपयोग के साथ हड़प्पा शहरी नियोजन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के पूरे क्षेत्र में धोलावीरा की अनूठी स्थिति को दर्शाती हैं।

पानी की उपलब्ध हर बूंद को इक्टठा करने के लिए डिज़ाइन की गई विस्तृत जल प्रबंधन प्रणाली लोगों की तेज़ भू-जलवायु परिवर्तनों के मुकाबले जीवित रहने की सरलता को दर्शाती है। मौसमी जलधाराओं, अल्प वर्षा और उपलब्ध भूमि से अलग किए गए पानी को बड़े पत्थरों के जलाशयों में संग्रहीत किया गया था जो पूर्वी और दक्षिणी किलेबंदी के साथ मौजूद हैं। पानी तक पहुंचने के लिए, कुछ पत्थर के कुएं, जो सबसे पुराने उदाहरणों में से एक हैं, नगर के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से मौजूद हैं, और इनमें से सबसे प्रभावशाली एक कुआं नगर में स्थित है। धोलावीरा के इस तरह के विस्तृत जल संरक्षण तरीके अद्वितीय हैं और प्राचीन दुनिया की सबसे कुशल प्रणालियों में से एक मानी जाती हैं।

पहेलीनुमा परत जहां सूर्य का आंतरिक रोटेशन प्रोफाइल बदलता है,की सैद्धांतिक व्याख्या

शिमला। लम्बे समय से यह बात ज्ञात थी कि सूर्य की भूमध्य रेखा ध्रुवों की तुलना में अधिक तेजी से घूमती है। बहरहाल, ध्वनि तरंग का उपयोग करते हुए सूर्य की आंतरिक रोटेशन की जांच करने से एक पहेलीनुमा परत का पता चला जहां सूर्य का रोटेशन प्रोफाइल बहुत तेजी से बदलता है। इस परत को नियर-सर्फेस शीयर लेयर (एनएसएसएल) कहा जाता है और इसका अस्तित्व सौर सतह के बहुत निकट मौजूद होता है जहां एंगुलर वेलोसिटी में बाह्य रूप से कमी होती है।

इस परत की व्याख्या की लम्बे समय तक जांच के बाद, भारतीय खगोलविदों ने इसके अस्तित्व के लिए पहली बार एक सैद्धांतिक व्याख्या पाई है। एनएसएसएल को समझना सनस्पॉट फॉर्मेशन, सौर चक्र जैसी कई सौर घटनाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है और यह अन्य तारों में भी ऐसी ही घटनाओं को समझने में सहायक होगा।

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च

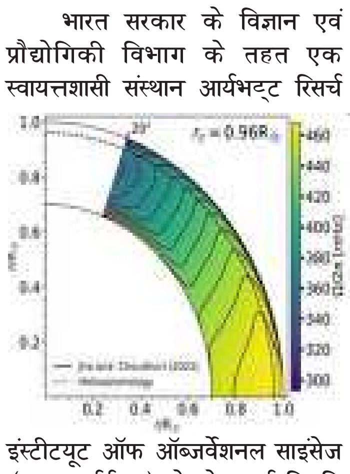

इंस्टीटयूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (एआरआईईएस) के शोधकर्ता बिभूति कुमार झा ने बैंगलुरू स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रो. अर्नब राय चौधरी के साथ मिलकर पहली बार सूर्य में एनएसएसएल के अस्तित्व की सैद्धांतिक व्याख्या की है। यह शोध पत्र रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के जर्नल मंथली नोटिसेज में प्रकाशित हुआ है।

अपने अध्ययन में उहोंने थर्मल विंड बैलेंस इक्वेशन नामक एक समीकरण का उपयोग किया। यह व्याख्या करती है कि किस प्रकार सौर ध्रुवों और भूमध्य रेखा, जिसे थर्मल विंड टर्म कहते हैं, के तापमान में मामूली अंतर का संतुलन सोलर डिफरेंशियल रोटेशन के कारण प्रतीत होने वाले सेंट्रिफुगल फोर्स के कारण होता है। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थिति केवल सूर्य के आंतरिक हिस्से में ही होती है और यह सौर्य सतह के निकट नहीं होती। इस शोध पत्र में, लेखकों ने प्रदर्शित किया है कि यह धारणा वास्तव में सतह के निकट भी होती है।

उन्होंने नोट किया कि अगर सौर सतह के निकट यह स्थिति सही है तो यह एनएसएसएल के अस्तित्व की व्याख्या कर सकती है जिसका अनुमान हेलियोसिज्मोलॉजी आधारित ऑब्जर्वेशन में लगाया जाता है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

प्रदेश कांग्रेस के पास बारह करोड़ कहां से आये यह खुलासा न होने से पत्र की विश्वसनीयता सवालों में

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को लेकर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमति सोनिया गांधी को पचास से अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र भेजा जाना इन दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्र में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर के खिलाफ कुछ आरोप लगाते हुए यह कहा गया है कि वह संगठन को चलाने में असमर्थ हैं। राठौर के अतिरिक्त पत्र में अन्य ग्यारह वरिष्ठ नेताओं कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी, रामलाल ठाकुर, जी एस बाली, सुखविन्दर सिंह सुक्खु, मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान, राजमाता प्रतिभा सिंह, सुधीर शर्मा, राजेन्द्र राणा और विप्लव ठाकुर को लेकर भी टिप्पणीयां की गयीं हैं। इसमें राम लाल ठाकुर को छोड़कर शेष सभी नेताओं की छवि पर कुछ न कुछ सवाल उठाते हुए यह कहने का प्रयास किया गया है कि यह लोग नेतृत्व के योग्य नहीं हैं। बड़ी चालाकी से इन नेताओं के बीच एक दिवार खड़ी करने का प्रयास किया गया है। इस समय प्रदेश में चार उपचुनाव होनें हैं और सभी दल इन चुनावों की तैयारियों में लग गये हैं। इन उपचुनावों के बाद अगले वर्ष नगर-निगम शिमला के चुनाव होने हैं। इस नगर निगम को प्रदेश की मिनी विधानसभा के रूप में देखा जाता है। इसके परिणामों का असर विधानसभा चुनावों पर पड़ता है जो इसके बाद होंगे। इस समय नगर निगम शिमला पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा के पार्षदों ने ही अपनी मेयर के खिलाफ किस कदर मोर्चा खोल रखा है वह सबके सामने आ चुका है। इससे नगर निगम से लेकर विधानसभा तक का आकलन करना आसान हो जाता है। इस परिदृश्य में कागेस पार्टी को लेकर इस समय लिखे गये पत्र का मतलब आसानी से समझा जा सकता है।

इसी परिपेक्ष में यदि पत्र के तथ्यों पर विचार किया जाये तो इसमें सबसे बड़ा आरोप अध्यक्ष के खिलाफ यह लगाया गया है कि उसने इस कोरोना काल में 12 करोड़ का जाली खर्च किया जाना दिखाया है। इसके लिये फर्जी बिल तैयार करने का आरोप है। इस आरोप पर विचार करने पर सबसे पहले ता यह सामने आता है कि आरोप लगाने ने यह खुलासा नहीं किया है कि प्रदेश ईकाई के पास यह 12 करोड़ आये कहां से? क्या केन्द्र ने दिये या कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठे किये गये। क्या यह बिल बनाकर केन्द्र को भेजे जाने थे और केन्द्र ने यह पैसा प्रदेश को देना था? क्या यह पैसा यदि आना भी था तो क्या पार्टी के खाते में आना था या कुलदीप राठौर के नीजि खाते में आना था। इन स्वभाविक सवालों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बारह करोड़ का आरोप केवल गंभीरता लाने के लिये ही लगाया गया है। वैसे यह बारह करोड़ का जिक्र एक समय मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर भी कर चुके हैं। वैसे इस पत्र में जितने भी नेताओं की जिक्र किया गया है उनमें से अधिकांश के खिलाफ भाजपा के आरोप पत्रों में आरोप रहे हैं। कुलदीप राठौर कभी विधायक या मन्त्री नहीं रहे हैं इस नाते वह आरोपों से बचे हुए हैं। दूसरी और भाजपा की कार्यशैली ही यह है कि वह आरोपों और जांच ऐजैन्सीयों के सहारे ही अपने विरोधियों पर हावी होने

एक बार जयराम भी कर चुके हैं बारह करोड़ का जिक्र क्या कांग्रेस पत्र लिखने वालों को चिन्हित कर पायेगी

का प्रयास करती है। 2014 और 2019 के चुनावों में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी से लेकर नीचे प्रदेश नेताओं तक ने कैसे स्व. वीरभद्र के खिलाफ आयकर, ईडी और सीबीआई द्वारा बनाये गये केसों को उछाला था यह पूरा प्रदेश जानता है।

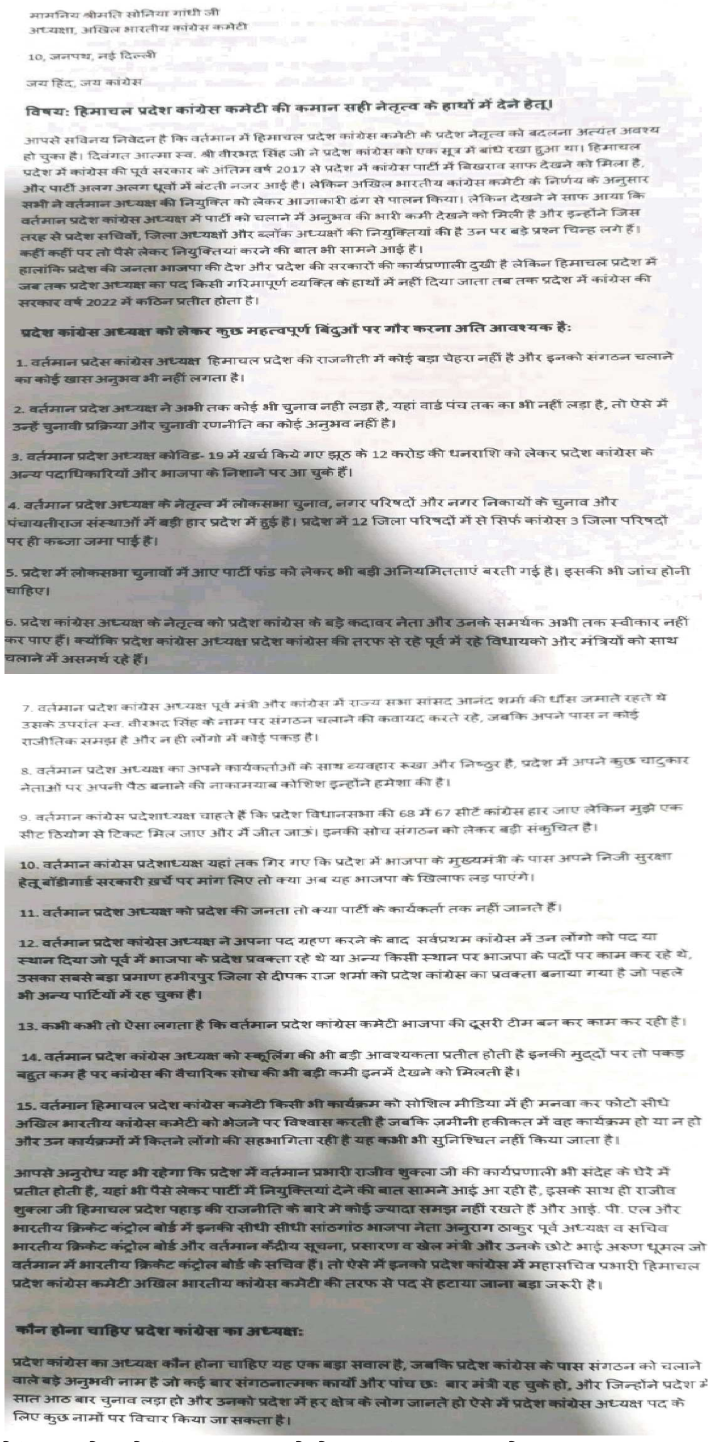
मामनिय श्रीमति सोनिया गांधी जी
अध्यक्षा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

10, जनपथ, नई दिल्ली

जय हिंद, जय कांग्रेस

विषय: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सही नेतृत्व के हाथों में देने हेतु।

आपसे सविनय निवेदन है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश नेतृत्व को बदलना अत्यंत अवश्य हो चुका है। दिवंगत आत्मा स्व. श्री वीरभद्र सिंह जी ने प्रदेश कांग्रेस को एक सूत्र में बांधे रखा हुआ था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पूर्व सरकार के अंतिम वर्ष 2017 से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में बिखराव साफ देखने को मिला है, और पार्टी अलग अलग धूवों में बंटती नजर आई है। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय के अनुसार सभी ने वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आज्ञाकारी ढंग से पालन किया। लेकिन देखने ने साफ आया कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष में पार्टी को चलाने में अनुभव की भारी कमी देखने को मिली है और इन्होंने जिस तरह से प्रदेश सचिवों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां की है उन पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हैं। कहीं कहीं पर तो पैसे लेकर नियुक्तियां करने की बात भी सामने आई है।
हालांकि प्रदेश की जनता भाजपा की देश और प्रदेश की सरकारों की कार्यप्रणाली दुखी है लेकिन हिमाचल प्रदेश में जब तक प्रदेश अध्यक्ष का पद किसी गरिमापूर्ण व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जाता तब तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वर्ष 2022 में कठिन प्रतीत होता है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करना अति आवश्यक है:

1. वर्तमान प्रदेस कांग्रेस अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश की राजनीती में कोई बड़ा चेहरा नहीं है और इनको संगठन चलाने का कोई खास अनुभव भी नहीं लगता है।

2. वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने अभी तक कोई भी चुनाव नही लड़ा है, यहां वार्ड पंच तक का भी नहीं लड़ा है, तो ऐसे में उन्हें चुनावी प्रक्रिया और चुनावी रणनीति का कोई अनुभव नहीं है।

3. वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कोविड- 19 में खर्च किये गए झूठ के 12 करोड़ की धनराशि को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अन्य पदाधिकारियों और भाजपा के निशाने पर आ चुके हैं।

4. वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव, नगर परिषदों और नगर निकायों के चुनाव और पंचायतीराज संस्थाओं में बड़ी हार प्रदेश में हुई है। प्रदेश में 12 जिला परिषदों में से सिर्फ कांग्रेस 3 जिला परिषदों पर ही कब्जा जमा पाई है।

5. प्रदेश में लोकसभा चुनावों में आए पार्टी फंड को लेकर भी बड़ी अनियमितताएं बरती गई है। इसकी भी जांच होनी चाहिए।

6. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व को प्रदेश कांग्रेस के बड़े कदावर नेता और उनके समर्थक अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस की तरफ से रहे पूर्व में रहे विधायको और मंत्रियों को साथ चलाने में असमर्थ रहे हैं।

7. वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री और कांग्रेस में राज्य सभा सांसद आनंद शर्मा की धौंस जमाते रहते थे उसके उपरांत स्व. वीरभद्र सिंह के नाम पर संगठन चलाने की कवायद करते रहे, जबकि अपने पास न कोई राजीतिक समझ है और न ही लोगो में कोई पकड़ है।

8. वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का अपने कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार रूखा और निष्ठुर है, प्रदेश में अपने कुछ चाटुकार नेताओं पर अपनी पैठ बनाने की नाकामयाब कोशिश इन्होंने हमेशा की है।

9. वर्तमान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चाहते हैं कि प्रदेश विधानसभा की 68 में 67 सीटें कांग्रेस हार जाए लेकिन मुझे एक सीट ठियोग से टिकट मिल जाए और मैं जीत जाऊं। इनकी सोच संगठन को लेकर बड़ी संकुचित है।

10. वर्तमान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष यहां तक गिर गए कि प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री के पास अपने निजी सुरक्षा हेतु बॉडीगार्ड सरकारी ख़र्च पर मांग लिए तो क्या अब यह भाजपा के खिलाफ लड़ पाएंगे।

11. वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश की जनता तो क्या पार्टी के कार्यकर्ता तक नहीं जानते हैं।

12. वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना पद ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कांग्रेस में उन लोगो को पद या स्थान दिया जो पूर्व में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रहे थे या अन्य किसी स्थान पर भाजपा के पदों पर काम कर रहे थे, उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमीरपुर जिला से दीपक राज शर्मा को प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया गया है जो पहले भी अन्य पार्टियों में रह चुका है।

13. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी भाजपा की दूसरी टीम बन कर काम कर रही है।

14. वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को स्कूलिंग की भी बड़ी आवश्यकता प्रतीत होती है इनकी मुद्दों पर तो पकड़ बहुत कम है पर कांग्रेस की वैचारिक सोच की भी बड़ी कमी इनमें देखने को मिलती है।

15. वर्तमान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी भी कार्यक्रम को सोशिल मीडिया में ही मनवा कर फोटो सीधे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजने पर विश्वास करती है जबकि ज़मीनी हकीकत में वह कार्यक्रम हो या न हो और उन कार्यक्रमों में कितने लोगो की सहभागिता रही है यह कभी भी सुनिश्चित नहीं किया जाता है।

आपसे अनुरोध यह भी रहेगा कि प्रदेश में वर्तमान प्रभारी राजीव शुक्ला जी की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में प्रतीत होती है, यहां भी पैसे लेकर पार्टी में नियुक्तियां देने की बात सामने आई आ रही है, इसके साथ ही राजीव शुक्ला जी हिमाचल प्रदेश पहाड़ की राजनीति के बारे मे कोई ज्यादा समझ नहीं रखते हैं और आई. पी. एल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में इनकी सीधी सीधी सांठगांठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर पूर्व अध्यक्ष व सचिव भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और वर्तमान केंद्रीय सूचना, प्रसारण व खेल मंत्री और उनके छोटे भाई अरुण धूमल जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। तो ऐसे में इनको प्रदेश कांग्रेस में महासचिव प्रभारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पद से हटाया जाना बड़ा जरूरी है।

कौन होना चाहिए प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष:

प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए यह एक बड़ा सवाल है, जबकि प्रदेश कांग्रेस के पास संगठन को चलाने वाले बड़े अनुभवी नाम है जो कई बार संगठनात्मक कार्यों और पांच छः बार मंत्री रह चुके हो, और जिन्होंने प्रदेश मे सात आठ बार चुनाव लड़ा हो और उनको प्रदेश में हर क्षेत्र के लोग जानते हो ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कुछ नामों पर विचार किया जा सकता है।

लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के पास ऐसा कोई हथियार कांग्रेस और उसके नेताओं के खिलाफ नहीं होगा। कानून के जानकारों के मुताबिक वीरभद्र के खिलाफ बनाये गये केसों का परिवार पर कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि सभी मामलों में मुख्य दोषी वही थे।

इस वस्तुस्थिति में यह पत्र लिखकर कांग्रेस को कमज़ोर करने का जो प्रयास किया गया है उससे कांग्रेस का नुकसान होने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कुलदीप राठौर ने जनवरी 2019 में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सम्भाली थी। उस समय राठौर के नाम पर वीरभद्र सिंह, आन्न्द शर्मा, आशा कुमारी और मुकेश अग्निहोत्री सभी ने लिखित में सहमति दी है। उस समय भी हाई कमान के सामने सभी नाम थे और उन पर हाई कमान की सहमति नहीं थी। इसलिये अब अध्यक्ष को परफारमैन्स के आधार पर ही बदलने की बात आ सकती है। राठौर ने जिम्मेवारी संभालने के बाद 2019 के लोकसभा और फिर दो उपचुनाव हुए हैं। लोकसभा चुनाव में किस तरह स्व. वीरभद्र और पंडित सुखराम के अहंकार का टकराव रहा है उससे चुनाव में नुकसान होना तय था, शैल ने उस समय यह स्पष्ट लिखवा हुआ है। लोकसभा चुनाव लड़ने तक के लिये वरिष्ठ नेता तैयार नहीं थे। उपचुनाव तक वही स्थिति बनी रही। लेकिन इसके बाद जब राष्ट्रीय स्तर पर हालात बदलने लगे तो उसका लाभ प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में मिला। जब चार नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़े गये तब दो निगमों में हुई सीधी जीत ने पार्टी और उसके सामूहिक नेतृत्व की क्षमता पर मोहर लगा दी है। इस समय मोदी और भाजपा के खिलाफ जासूसी प्रकरण तथा किसान आन्दोलन से राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता जा रहा है उससे आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ मिलेगा। फिर जिन राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच तीसरा कोई नहीं है वहीं पर कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना कठिन है। हिमाचल में तीसरा कोई नहीं है ऐसे में इस तरह के पत्रों और कुछ तीसरों को खड़ा करने जैसे प्रयास आने वाले दिनों में देखने को मिलते रहेंगे ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस ऐसी चुनौतियों का कैसे सामना करेगी यह देखना दिलचस्प होगा।

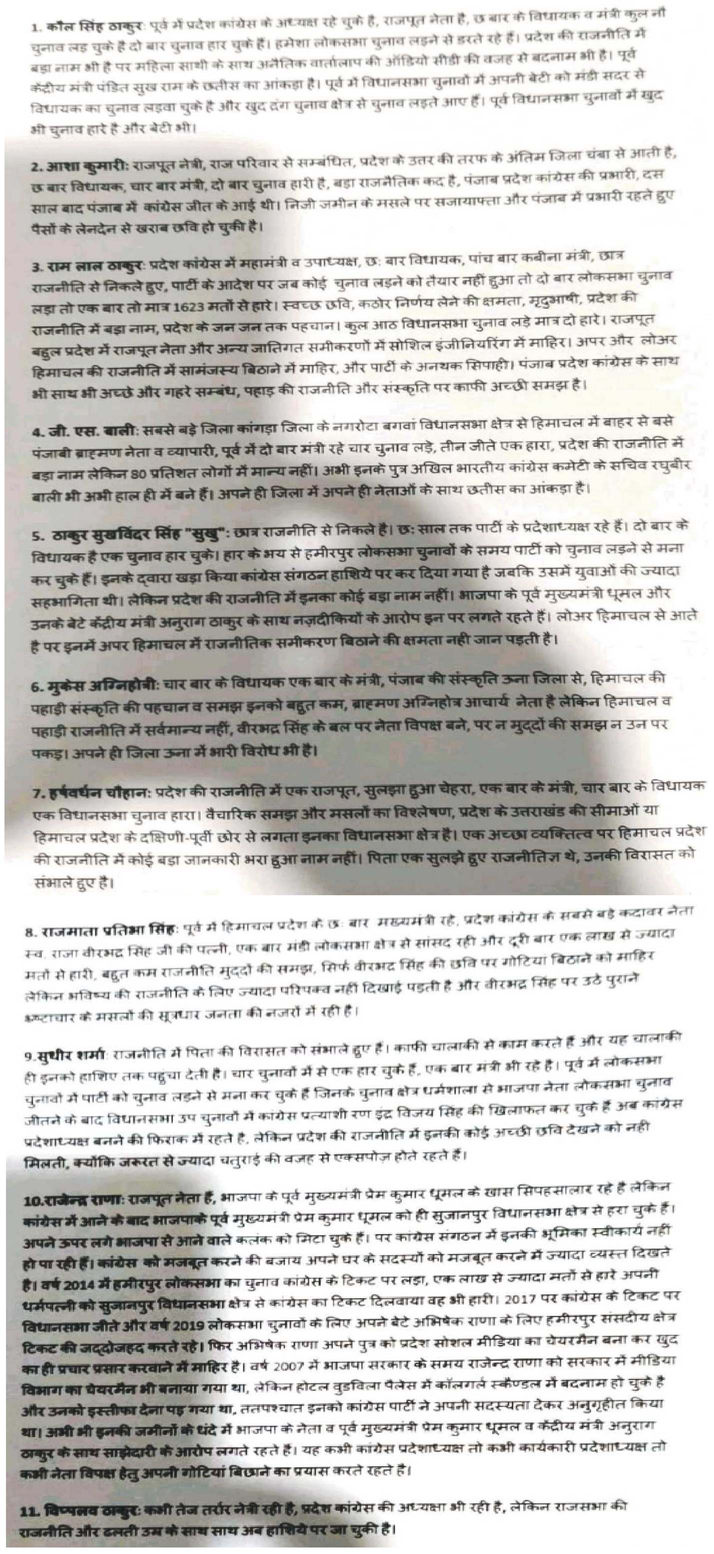
1. **कौल सिंह ठाकुर:** पूर्व में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे चुके है, राजपूत नेता है, छ बार के विधायक व मंत्री कुल नौ चुनाव लड़ चुके है दो बार चुनाव हार चुके हैं। हमेशा लोकसभा चुनाव लड़ने से डरते रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम भी है पर महिला साथी के साथ अनैतिक वार्तालाप की ऑडियो सीडी की वजह से बदनाम भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुख राम के छतीस का आंकड़ा है। पूर्व में विधानसभा चुनावों में अपनी बेटी को मंडी सदर से विधायक का चुनाव लड़वा चुके है और खुद दंग चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ते आए हैं। पूर्व विधानसभा चुनावों में खुद भी चुनाव हारे है और बेटी भी।

2. **आशा कुमारी:** राजपूत नेत्री, राज परिवार से सम्बंधित, प्रदेश के उत्तर की तरफ के अंतिम जिला चंबा से आती है, छ बार विधायक, चार बार मंत्री, दो बार चुनाव हारी है, बड़ा राजनैतिक कद है, पंजाब प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी, दस साल बाद पंजाब में कांग्रेस जीत के आई थी। निजी जमीन के मसले पर सजायाफ्ता और पंजाब में प्रभारी रहते हुए पैसों के लेनदेन से खराब छवि हो चुकी है।

3. **राम लाल ठाकुर:** प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री व उपाध्यक्ष, छः बार विधायक, पांच बार कबीना मंत्री, छात्र राजनीति से निकले हुए, पार्टी के आदेश पर जब कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ तो दो बार लोकसभा चुनाव लड़ा तो एक बार तो मात्र 1623 मतों से हारे। स्वच्छ छवि, कठोर निर्णय लेने की क्षमता, मृदुभाषी, प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम, प्रदेश के जन जन तक पहचान। कुल आठ विधानसभा चुनाव लड़े मात्र दो हारे। राजपूत बहुल प्रदेश में राजपूत नेता और अन्य जातिगत समीकरणों में सोशिल इंजीनियरिंग में माहिर। अपर और लोअर हिमाचल की राजनीति में सामंजस्य बिठाने में माहिर, और पार्टी के अनथक सिपाही। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के साथ भी साथ भी अच्छे और गहरे सम्बंध, पहाड़ की राजनीति और संस्कृति पर काफी अच्छी समझ है।

4. **जी. एस. बाली:** सबसे बड़े जिला कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल में बाहर से बसे पंजाबी ब्राह्मण नेता व व्यापारी, पूर्व में दो बार मंत्री रहे चार चुनाव लड़े, तीन जीते एक हारा, प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम लेकिन 80 प्रतिशत लोगों में मान्य नहीं। अभी इनके पुत्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रघुबीर बाली भी अभी हाल ही में बने हैं। अपने ही जिला में अपने ही नेताओं के साथ छतीस का आंकड़ा है।

5. **ठाकुर सुखविंदर सिंह "सुखु":** छात्र राजनीति से निकले है। छः साल तक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। दो बार के विधायक है एक चुनाव हार चुके। हार के भय से हमीरपुर लोकसभा चुनावों के समय पार्टी को चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। इनके द्वारा खड़ा किया कांग्रेस संगठन हाशिये पर कर दिया गया है जबकि उसमें युवाओं की ज्यादा सहभागिता थी। लेकिन प्रदेश की राजनीति में इनका कोई बड़ा नाम नहीं। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और उनके बेटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ नज़दीकियों के आरोप इन पर लगते रहते हैं। लोअर हिमाचल से आते है पर इनमें अपर हिमाचल में राजनीतिक समीकरण बिठाने की क्षमता नही जान पड़ती है।

6. **मुकेश अग्निहोत्री:** चार बार के विधायक एक बार के मंत्री, पंजाब की संस्कृति ऊना जिला से, हिमाचल की पहाड़ी संस्कृति की पहचान व समझ इनको बहुत कम, ब्राह्मण अग्निहोत्र आचार्य नेता है लेकिन हिमाचल व पहाड़ी राजनीति में सर्वमान्य नहीं, वीरभद्र सिंह के बल पर नेता विपक्ष बने, पर न मुद्दों की समझ न उन पर पकड़। अपने ही जिला ऊना में भारी विरोध भी है।

7. **हर्षवर्धन चौहान:** प्रदेश की राजनीति में एक राजपूत, सुलझा हुआ चेहरा, एक बार के मंत्री, चार बार के विधायक एक विधानसभा चुनाव हारा। वैचारिक समझ और मसलों का विश्लेषण, प्रदेश के उत्तराखंड की सीमाओं या हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी छोर से लगता इनका विधानसभा क्षेत्र है। एक अच्छा व्यक्तित्व पर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा जानकारी भरा हुआ नाम नहीं। पिता एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ थे, उनकी विरासत को संभाले हुए है।

8. **राजमाता प्रतिभा सिंह:** पूर्व में हिमाचल प्रदेश के छः बार मख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े कदावर नेता स्व. राजा वीरभद्र सिंह जी की पत्नी, एक बार मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद रही और दूरी बार एक लाख से ज्यादा मतों से हारी, बहुत कम राजनीति मुद्दो की समझ, सिर्फ वीरभद्र सिंह की छवि पर गोटियां बिठाने को माहिर लेकिन भविष्य की राजनीति के लिए ज्यादा परिपक्व नहीं दिखाई पड़ती है और वीरभद्र सिंह पर उठे पुराने भ्र्ष्टाचार के मसलों की सूत्रधार जनता की नजरों में रही है।

9. **सुधीर शर्मा**: राजनीति में पिता की विरासत को संभाले हुए हैं। काफी चालाकी से काम करते हैं और यह चालाकी ही इनको हाशिए तक पहुंचा देती है। चार चुनावों में से एक हार चुके है, एक बार मंत्री भी रहे है। पूर्व में लोकसभा चुनावों में पार्टी को चुनाव लड़ने से मना कर चुके है जिनके चुनाव क्षेत्र धर्मशाला से भाजपा नेता लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा उप चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी रण इंद्र विजय सिंह की खिलाफत कर चुके हैं अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनने की फिराक में रहते है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में इनकी कोई अच्छी छवि देखने को नही मिलती, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चतुराई की वजह से एक्सपोज़ होते रहते हैं।

10. **राजेन्द्र राणा:** राजपूत नेता हैं, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के खास सिपहसालार रहे है लेकिन कांग्रेस में आने के बाद भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को ही सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से हरा चुके हैं। अपने ऊपर लगे भाजपा से आने वाले कलंक को मिटा चुके हैं। पर कांग्रेस संगठन में इनकी भूमिका स्वीकार्य नहीं हो पा रही हैं। कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय अपने घर के सदस्यों को मजबूत करने में ज्यादा व्यस्त दिखते है। वर्ष 2014 में हमीरपुर लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, एक लाख से ज्यादा मतों से हारे अपनी धर्मपत्नी को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दिलवाया वह भी हारी। 2017 पर कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा जीते और वर्ष 2019 लोकसभा चुनावों के लिए अपने बेटे अभिषेक राणा के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र टिकट की जद्दोजहद करते रहे। फिर अभिषेक राणा अपने पुत्र को प्रदेश सोशल मीडिया का चेयरमैन बना कर खुद का ही प्रचार प्रसार करवाने में माहिर है। वर्ष 2007 में भाजपा सरकार के समय राजेन्द्र राणा को सरकार में मीडिया विभाग का चेयरमैन भी बनाया गया था, लेकिन होटल वुडविला पैलेस में कॉलगर्ल स्कैण्डल में बदनाम हो चुके है और उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, ततपश्चात इनको कांग्रेस पार्टी ने अपनी सदस्यता देकर अनुगृहीत किया था। अभी भी इनकी जमीनों के धंदे में भाजपा के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साझेदारी के आरोप लगते रहते हैं। यह कभी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तो कभी कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष तो कभी नेता विपक्ष हेतु अपनी गोटियां बिछाने का प्रयास करते रहते हैं।

11. **विप्पलव ठाकुर:** कभी तेज तर्रार नेत्री रही है, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही है, लेकिन राजसभा की राजनीति और ढलती उम्र के साथ साथ अब हाशिये पर जा चुकी है।

ममता ने जांच आयोग गठित

...पृष्ठ 1 का शेष

क्योंकि फोन तो हैकर आप्रेट कर रहा है। इसी प्रकरण में यह सामने आ चुका है कि जब राफेल मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय मे चल रही थी तब मुख्य न्यायधीश गागोई के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला और उसके परिजनों के फोन हैक हो चुके थे। आज इसी कारण से राफेल फैसले को जनता सन्देह से देख रही है। आज यह स्पाईवेयर अपने राजनीतिक विरोधीयों के खिलाफ सरकार का बड़ा हथियार माना जा रहा है। आज यदि मोदी सरकार ऐसा कर रही है तो कल सरकार बदलने पर दूसरी सरकार भी ऐसा ही करेगी। आज यदि केन्द्र सरकार इसे खरीद रही है तो क्या कल राज्य सरकारें ऐसी ही खरीद का प्रयास नहीं करेंगी। क्या आतंकी संगठन इसे लेने का प्रयास नहीं करेंगे। जब ईज़रायल और फ्रांस यह जांच करवा रहे हैं तब भारत सरकार का इस जांच से इन्कार करना कई कड़े सवालों को जन्म देता है। ऐसे में ममता द्वारा यह जांच बैठाने के निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिये। क्योंकि जब यह जांच आगे बढ़ेगी तो मोदी सरकार के पास और बड़ी जांच बैठाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहेगा।